घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 271- शनिवार 01- अगस्त 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

हैदराबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई...

पीएम मोदी के एआई-मॉर्फ्ड वीडियो मामले में Meta इंडिया हेड समेत कई पर FIR

नई दिल्ली,31 जुलाई 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े कथित एआई-जनरेटेड और मॉर्फ्ड वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के मामले में हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा के इंडिया हेड अरुण श्रीनिवास,कई सोशल मीडिया अकाउंट संचालकों और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामला तेलंगाना के दो शिकायतकर्ताओं की शिकायत पर दर्ज किया गया है,जिनका आरोप है कि एआई तकनीक से तैयार किए गए वीडियो और तस्वीरों के जरिए प्रधानमंत्री को आपत्तिजनक,भ्रामक और अपमानजनक तरीके से पेश किया गया। पुलिस के अनुसार, जांच का मुख्य फोकस यह पता लगाना है कि फर्जी वीडियो सबसे पहले किसने अपलोड किए,किन खातों से इन्हें वायरल किया गया और इसके पीछे क्या उद्देश्य था। साथ ही भारतीय न्याय संहिता और आईटी कानून के तहत संभावित उल्लंघनों की भी जांच की जा रही है। पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट्स के संचालकों को आरोपी बनाया है, जबकि मेटा इंडिया हेड को सह-आरोपी के रूप में नामजद किया गया है। इस कार्रवाई से पहले हैदराबाद पुलिस ने मेटा को समन जारी कर एआई आधारित फर्जी कंटेंट की पहचान और हटाने की व्यवस्था पर जवाब मांगा था। कंपनी के प्रतिनिधियों ने जांच एजेंसियों के सामने कंटेंट मॉडरेशन नीति की जानकारी दी। विवाद के बाद मेटा ने सरकार को भरोसा दिलाया है कि प्रधानमंत्री सहित प्रमुख वीआईपी अकाउंट्स की निगरानी और समीक्षा अब वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में होगी।

कैबिनेट ने 'प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना' को मंजूरी दी

जलाशयों पर विकसित होगी 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सौर क्षमता

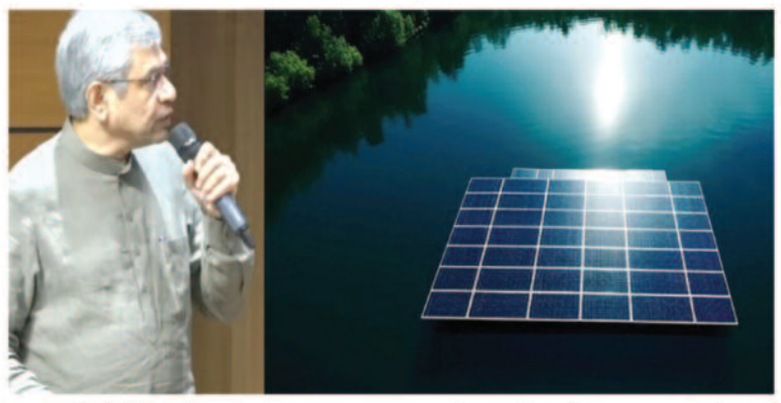

नई दिल्ली,31 जुलाई 2026। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को 'प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना (पीएम-एसएसवाई)' को मंजूरी दे दी। 5,070 करोड़ रुपये की इस योजना के तहत देश के जलाशयों,बांधों,झीलों,नहरों और अन्य जल निकायों की सतह का उपयोग कर 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर ऊर्जा क्षमता विकसित की जाएगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में कहा कि देश में जल निकायों की सतह का उपयोग सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि बांध, झील, नहर और अन्य जलाशयों पर फ्लोटिंग सोलर परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी,जिससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा और भूमि पर अतिरिक्त दबाव भी नहीं पड़ेगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (एनआईएसई) के आकलन के अनुसार देश में जलाशयों और अन्य उपयुक्त जल निकायों पर करीब 102 गीगावाट (लगभग एक लाख मेगावाट) फ्लोटिंग सोलर क्षमता विकसित करने की संभावना है। इस योजना के पहले चरण में 5,000 मेगावाट क्षमता विकसित की जाएगी। योजना के तहत वर्ष 2026-27 से 2030-31 के बीच फ्लोटिंग सोलर परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। इनके साथ कम से कम दो घंटे की ऊर्जा भंडारण प्रणाली भी होगी,जिसकी कुल क्षमता 10,000 मेगावाट घंटा (एमडब्ल्यूएच) होगी। परियोजनाओं के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता का वितरण वर्ष 2032-33 तक जारी रहेगा। सरकार प्रत्येक पात्र फ्लोटिंग सोलर परियोजना को सफलतापूर्वक शुरू होने पर प्रति मेगावाट एक करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता देगी। इसके अलावा व्यवहार्यता अध्ययन,जल की गहराई और पर्यावरण संबंधी अध्ययन जैसी प्रारंभिक तैयारियों के लिए प्रति परियोजना 50 लाख रुपये तक की सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को लाभ मिलेगा। वर्तमान में देश में फ्लोटिंग सोलर क्षमता लगभग 700 मेगावाट है, जिसे बढ़ाकर 5,000 मेगावाट किया जाएगा। इससे जलाशयों और औद्योगिक तालाबों का बेहतर उपयोग होगा तथा भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता कम होगी। योजना के तहत हर वर्ष लगभग एक करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आने का अनुमान है। इसके अलावा परियोजनाओं की पूरी श्रृंखला में 16 से 17 हजार प्रत्यक्ष और समकक्ष पूर्णकालिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। सरकार का मानना है कि यह योजना फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म,सोलर सेल,मॉड्यूल और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देगी तथा आत्मनिर्भर भारत और स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य को मजबूत करेगी।

किसान,खेल,समुद्र और ऊर्जा से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में उक्त प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिमंडल ने 5,070 करोड़ रुपये के कुल बजट परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना (पीएम-एसएसवाई) को मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य कम से कम 10,000 मेगावाट भंडारण क्षमता वाले ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ 5,000 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट विकसित करना है। पीएम-किसान योजना 2030-31 तक जारी रहेगी। इसके लिए कुल 3.15 लाख करोड़ रुपये का वित्तीय आवंटन किया गया है। योजना के तहत किसानों को सीधे 4.47 लाख करोड़ रुपये से अधिक हस्तांतरित किए जा चुके हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना 'समुद्र मंथन' को मंजूरी दी है। इसके लिए वित्त वर्ष 2030-31 तक कार्यान्वयन हेतु 84,084 करोड़ रुपये का स्वीकृत परिव्यय निर्धारित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य भारत की विशाल अपतटीय ऊर्जा क्षमता का दोहन करना और देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ संशोधित 'खेलो इंडिया योजना' को मंजूरी दी है। वित्त वर्ष 2026-31 के लिए राष्ट्रीय खेल संघों को सुदृढ़ सहायता (एएनएसएफ) योजना को भी मंजूरी दी गई है।

अपतटीय ऊर्जा क्षमता के दोहन के लिए 'समुद्र मंथन' योजना को मंजूरी

केन्द्र सरकार ने देश की विशाल अपतटीय ऊर्जा क्षमता का दोहन करने के लिए एक योजना को मंजूरी दी है जिससे तेल के भंडार में 60 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक की वृद्धि होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना 'समुद्र मंथन' को मंजूरी दी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र योजना के लिए वित्त वर्ष 2030-31 तक 84,084 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया केन्द्र में पत्रकार वार्ता में कहा कि यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने,घरेलू अन्वेषण और उत्पादन में तेजी लाने,तकनीकी नेतृत्व को बढ़ावा देने और विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। योजना के तहत अपतटीय अन्वेषण गतिविधियों में पर्याप्त वृद्धि की जाएगी। साथ ही घरेलू तेल और गैस उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होंगे।

विपक्षी सांसद बैनर लेकर पहुंचे अमित शाह संसद से गायब क्यों?

संसद में पप्पू यादव पुजारी बनकर पहुंचे,राहुल गांधी ने चंदा दिया,राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर विपक्ष का प्रदर्शन

नई दिल्ली,31 जुलाई 2026। विपक्षी सांसदों ने शुक्रवार को संसद परिसर में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर प्रदर्शन किया। सांसद पप्पू यादव पुजारी के वेश में दानपेटी लेकर पहुंचे। राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों ने दानपेटी में चंदा डाला। साथ ही विपक्षी सांसद बैनर लेकर पहुंचे जिसमें 'अमित शाह संसद से गायब क्यों' लिखा हुआ था। इधर, लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई,लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। 12 बजे दोबारा शुरू होने पर लोकसभा में जन्म-मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) बिल, 2026 ध्वनि मत से पास हुआ। लोकसभा और राज्यसभा तीन अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई हैं। वहीं,कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के संसद में दिए गए बयान को लेकर उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया है। सिंह ने कहा था कि जंतर-मंतर और संसद मार्च में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग नहीं हुई थी।

लोकसभा तीन अगस्त तक स्थगित

केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में जन्म-मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) बिल, 2026 पारित करने का प्रस्ताव रखा। बिल ध्वनि मत से पास हुआ। इसके बाद विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा तीन अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई।

रिजिजू बोले...सदन में बिल पर चर्चा करें,हंगामा नहीं

किरेन रिजिजू ने कहा कि हम चाहते हैं कि भविष्य में ऐसा न हो। आप चर्चा में शामिल नहीं होते और बाहर जाकर कहते हैं कि सरकार चर्चा नहीं कराती। अगला बिल लेकर आएंगे और आप हंगामा करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। चर्चा करें,हंगामा ना करें।

जेन-जी को डराया जा रहा : राहुल

राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक्स पर लिखा,'पीएम मोदी और अमित शाह आप Gen-G को चुप रहने के लिए धमका नहीं सकते। पहले आपने उनकी हड्डियां तोड़ीं।' उन्होंने कहा, 'अब आप एफआईआर कर रहे हैं। उनके अकाउंट बंद कर रहे हैं। आप भारत का अतीत हैं। भारत के भविष्य के साथ कैसा व्यवहार करते हैं,इस बारे में सावधान रहें।'

स्पेन में घुसने पहुंचे 60 हजार प्रवासी,34 की मौत

मोरक्को से समुद्र में तैरकर आए थे,बॉर्डर पर सेना ने रोका तो भगदड़ मची

सिउटा,31 जुलाई 2026। स्पेन में जबरन घुसने की कोशिश के दौरान 18 अफ्रीकी प्रवासियों की मौत हो गई। घटना तब हुई,जब 3 हजार प्रवासी एकसाथ स्पेनिश शहर स्यूटा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। सीमा पर पुलिस की घेराबंदी और सुरक्षा बाड़ के बीच संकरे रास्तों के कारण लोग एक-दूसरे पर गिर पड़े। भीड़ में दबने,दम घुटने और समुद्र में डूबने के कारण यह हादसा हुआ। इस दौरान स्पेन और मोरक्को के 100 से ज्यादा सैनिक भी घायल हो गए। स्पेनिश सरकार ने बताया कि 24 घंटे में मोरक्को की तरफ से करीब 60 हजार लोग तैरकर या पैदल चलकर स्यूटा में घुस चुके है। यह शहर की आबादी का 70% है।

समुद्र और सीमा रास्तों से हजारों लोगों ने की घुसपैठ की कोशिश

प्राप्त जानकारी के अनुसार,बड़ी संख्या में प्रवासी उत्तरी मोरक्को से स्यूटा में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे। इनमें अधिकतर युवा पुरुष शामिल थे,लेकिन कई महिलाएं और छोटे बच्चों वाले परिवार भी इस जोखिम भरे सफर का हिस्सा बने। कुछ लोग समुद्र के रास्ते स्पेन पहुंचे,जबकि कुछ ने सीमा की बाड़ को पार करने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में बड़ी संख्या में लोगों को समुद्र तट और सड़कों पर भागते हुए देखा गया,जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा।

स्पेन सरकार ने सुरक्षा के लिए सेना भेजने का लिया फैसला : स्थिति को नियंत्रित करने के लिए स्पेन सरकार ने स्यूटा में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने का फैसला किया है। सरकार ने सिविल गार्ड की मदद के लिए सेना की तैनाती की घोषणा की। स्पेन के प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज ने भी गृह मंत्री फर्नांडो ग्रांदे-मार्लास्का के साथ स्यूटा जाने की योजना बनाई। अधिकारियों का कहना है कि प्राथमिकता सीमा पर नियंत्रण स्थापित करना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। स्यूटा सीमा पर तैनात सिविल गार्ड अधिकारियों के संगठन के प्रमुख राशिद स्बीही ने स्थिति को बेहद गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि हालात पूरी तरह अराजक हो चुके हैं और हजारों लोग सीमा पार करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अनुसार,इतनी बड़ी संख्या में लोगों के एक साथ पहुंचने से सीमा व्यवस्था पर भारी दबाव पड़ा है। सुरक्षा बलों के लिए भीड़ को नियंत्रित करना बड़ी चुनौती बन गया है।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश...रूस-यूक्रेन युद्ध में मारे गए भारतीयों के परिवारों की मदद करे केंद्र

नई दिल्ली,31 जुलाई 2026। रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान नौकरी का झांसा देकर रूस भेजे गए और बाद में युद्ध क्षेत्र में पहुंचा दिए गए भारतीय नागरिकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अहम निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा...'विदेश मंत्रालय में एक समर्पित नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो पीड़ित परिवारों से सीधे संपर्क में रहेगा।' अदालत ने कहा कि युद्ध में मारे गए,घायल या लापता भारतीयों के परिजन पहले से ही मानसिक और आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, इसलिए सरकार उनकी हरसंभव सहायता सुनिश्चित करे। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत,न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने निर्देश दिया कि'युद्ध में मारे गए भारतीयों की पहचान के लिए डीएनए सैंपल का मिलान कराया जाएगा।' साथ ही'नई दिल्ली स्थित रूसी दूतावास के समक्ष मुआवजा क्लेम दाखिल कराने में विदेश मंत्रालय परिवारों की मदद करेगा।' अदालत ने यह भी कहा कि 'पीड़ित परिवारों को सभी जरूरी जानकारी और प्रक्रियाएं उनकी मातृभाषा या स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराई जाएंगी। '

नेपाल के सुनसरी हिंसा पर 7 सूत्रीय समझौता मृतकों को शहीद का दर्जा और मुआवजा

नई दिल्ली,31 जुलाई 2026। नेपाल के सुनसरी जिले के कप्तानगंज क्षेत्र में कांवर यात्रा के दौरान हुई हिंसक घटना के बाद पूरे मधेश क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। रिपोर्टों के अनुसार,कांवरियों के एक जत्थे पर कथित हमले के बाद दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई,जो देखते ही देखते हिंसक रूप ले गई। इस दौरान गोलीबारी की भी सूचना सामने आई। घटना में एक कांवरिया श्रद्धालु की मौत हो गई,जबकि एक दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया और कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। हालांकि,घटना से जुड़े आरोपों और परिस्थितियों की आधिकारिक जांच जारी है। घटना के विरोध में जनकपुरधाम में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। हिंदू सम्राट सेना,नेपाल हिंदू स्वयं सेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद,साधु-संतों और स्थानीय नागरिकों ने विभिन्न स्थानों पर रैलियां निकालकर विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों ने जानकी चौक,राम चौक,जनक चौक, रामानंद चौक,मिल्स एरिया और पिड़ारी चौक सहित कई प्रमुख चौराहों पर टायर जलाए और नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के पुतले भी जलाए गए। पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। जब प्रदर्शन उग्र होने लगा और कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बढ़ी।

घायल सब-इंस्पेक्टर की बेटी मीडिया से बोली... कॉकरोच प्रोटेस्ट में कई हिंसक प्रवृत्ति के लड़के थे

नई दिल्ली,31 जुलाई 2026। राजधानी दिल्ली में हाल ही में 'कॉकरोच जनता पार्टी' के प्रदर्शन और'संसद चलो'मार्च के दौरान हुई हिंसा में घायल हुए पुलिसकर्मियों के परिवारों का दर्द अब सामने आया है। हिंसा में गंभीर रूप से चोटिल हुए जवानों के परिजनों ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर अपनी आपबीती बयां की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान परिजनों का भावुक रूप देखने को मिला। घायल पुलिसकर्मी के एक परिजन ने रोते हुए अपनी आपबीती सुनाई,'जब मेरे पिता उस दिन ड्यूटी के बाद घर लौटे,तो उनकी खाकी वर्दी खून से पूरी तरह लाल थी। उनके सिर और हाथों पर गंभीर चोटें थीं। दिल्ली पुलिस के एसीपी की पत्नी अवनीत कौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उस खौफनाक दिन को याद करते हुए बताया, '20 जुलाई की रात जब मेरे पति घायल अवस्था में घर पहुंचे,तो उनकी हालत देखकर मेरी रूह कांप गई। वह दृश्य मेरे और हमारी 2 साल की बेटी के लिए बेहद दर्दनाक और ट्रॉमेटिक था। मेरी मासूम बेटी अपने पिता को उस हालत में देखकर सहम गई थी।' प्रदर्शनकारियों के उग्र रवैये और पुलिस पर हुए हमले पर गंभीर सवाल उठाते हुए अवनीत कौर ने कहा,'लोग यह भूल जाते हैं कि एक पुलिस अधिकारी सिर्फ एक अकेला इंसान या वर्दी नहीं होता। उसके पीछे उसका एक परिवार होता है-उसकी पत्नी, छोटे बच्चे और बूढ़े माता-पिता, जो हर पल घर पर उसके सुरक्षित लौटने का इंतजार करते हैं।

'घायल सब-इंस्पेक्टर की बेटी ने रोते हुए बताया,'पुलिस में शामिल होने से पहले,मेरे पिता इंडियन नेवी में मरीन कमांडो थे। उन्होंने अपनी जिंदगी के 15 साल इंडियन नेवी को दिए। उस दिन मेरे पिता बैरिकेड्स पर तैनात थे,जहां बहुत भारी भीड़ मौजूद थी। पापा अक्सर घर पर बताते थे कि अब यह सिर्फ छात्रों का आंदोलन नहीं रह गया है,इसमें कुछ असामाजिक तत्व घुस चुके हैं।'उस खौफनाक दिन को याद करते हुए बेटी ने बताया,'25 तारीख को प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने मेरे पिता को जबरन खींच लिया और उन पर जानलेवा हमला कर दिया। उन्हें लगभग मार ही डाला गया था।

हमले के बाद वे 4 घंटे से भी ज्यादा समय तक मौके पर बेहोश पड़े रहे। बाद में जब उनकी टीम के लोग उन्हें किसी तरह बचाकर घर लाए,तो उनकी पूरी वर्दी खून से लथपथ थी। एक तरफ मेरे पिता अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे, उनकी वर्दी खून से सनी हुई थी,लेकिन जब मैंने सोशल मीडिया खोला तो देखकर दंग रह गई।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दिया इस्तीफा

नई दिल्ली,31 जुलाई 2026। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के अनुसार,उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए अपना इस्तीफा भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को सौंप दिया है। हालांकि,उनके इस्तीफे के पीछे की वास्तविक वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सकी है। शहजाद पूनावाला जल्द ही अपने इस्तीफे को लेकर आधिकारिक बयान जारी कर सकते हैं। इसी बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर उनके प्रोफाइल से भाजपा का उल्लेख हट गया है। हालांकि,उन्होंने अपने बायो में स्वयं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'आजीवन समर्थक'बताया है। वहीं, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर उन्हें अब भी भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता लिखा गया है। फिलहाल पार्टी की ओर से उनके इस्तीफे को लेकर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पेशे से वकील और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता शहजाद पूनावाला ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस से की थी। वर्ष 2017 में उन्होंने कांग्रेस की आंतरिक चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया था कि पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के उद्देश्य से प्रभावित की जा रही है। इस विवाद के बाद कांग्रेस नेतृत्व और उनके परिवार के कुछ सदस्यों, जिनमें उनके भाई तहसीन पूनावाला भी शामिल हैं,ने उनसे सार्वजनिक दूरी बना ली थी। इसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। भाजपा में शामिल होने के बाद शहजाद पूनावाला को राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी गई।

भरत तिवारी एनकाउंटर में एक्शन...

एसटीएफ जवान गिरफ्तार

बिहार,31 जुलाई 2026। राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में पुलिस ने एक बेहद महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। परिजनों के भारी आक्रोश और लगातार जारी विरोध-प्रदर्शनों के बाद,प्रशासन ने आखिरकार बड़ा कदम उठाते हुए भरत तिवारी पर गोली चलाने के आरोपी एसटीएफ जवान अक्षय कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक,कुछ दिनों पहले हुए इस एनकाउंटर के बाद से ही भरत तिवारी के परिजन और स्थानीय लोग इस पूरी घटना को संदिग्ध मान रहे थे।

परिजनों का आरोप था कि यह एक एकतरफा और फर्जी एनकाउंटर था। इसमें भरत तिवारी की जानबूझकर हत्या की गई। घटना के बाद से ही पीड़ित परिवार न्याय की मांग को लेकर अड़ा हुआ था। वे आरोपी एसटीएफ जवान की तुरंत गिरफ्तारी के लिए लगातार दबाव बना रहा थे।

दिल्ली दंगा...ताहिर हुसैन को उम्रकैद, 51 घाव और नाले में फेंका शव

कोर्ट बोला...घटना गंभीर,इसने समाज को झकझोर दिया

नई दिल्ली,31 जुलाई 2026। 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि यह बेहद गंभीर वारदात थी,जिसने समाज को झकझोर दिया। कोर्ट ने 13 जुलाई को ताहिर, नाजिम,काशिम,अनस और जावेद को हत्या, अपहरण,दंगा और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने का दोषी ठहराया था। वहीं,11 आरोपियों में से 6 को बरी कर दिया गया था। लोकल कोर्ट ने कहा -ताहिर हुसैन हथियारों से लैस उस भीड़ का हिस्सा थे,जो हिंदुओं के प्रति नफरत के कारण

दंगा,आगजनी और लूटपाट करने के लिए इकट्ठा हुई थी। जिसने बेरहमी से और लगातार हमला करके शर्मा की हत्या कर दी। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा था,'आरोपियों ने सारी हदें पार कर दीं। अंकित की मौत होने के बाद भी उन पर हमला जारी रखा गया। यह बेहद क्रूर और सुनियोजित हत्या थी। इसलिए दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। ताहिर हुसैन के वकील ने दलील दी थी कि हर हत्या के मामले में मौत की सजा नहीं दी जा सकती। किसी भी दोषी की अलग-अलग भूमिका साफ नहीं बताई गई। इसलिए यह मामला 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' की श्रेणी में नहीं आता। दिल्ली दंगा 23 फरवरी, 2020 से शुरू हुआ था। 25 फरवरी को आईबी अफसर अंकित शर्मा घर से बाहर निकले थे, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं आए। परिवार उनकी तलाश कर रहा था,तभी लोगों ने बताया कि उनका शव चांदबाग पुलिया के पास खजूरी खास नाले में देखा गया है।

संपादकीय

बस्तर : बंदूक की गूंज से विकास की दस्तक तक

क्या अब स्थायी शांति का समय है?

छत्तीसगढ़ का बस्तर कभी देश में नक्सल हिंसा का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था। दशकों तक यहां की पहचान घने जंगलों,आदिवासी संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य से अधिक नक्सली घटनाओं, सुरक्षा अभियानों और हिंसा से जुड़ी रही। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में परिस्थितियां तेजी से बदलती दिखाई दे रही हैं। सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई, नक्सलियों के खिलाफ सफल अभियान, आत्मसमर्पण की बढ़ती संख्या और दूरस्थ क्षेत्रों तक प्रशासन की पहुंच ने यह संकेत दिया है कि बस्तर एक नए दौर की ओर बढ़ रहा है। हालांकि,यह भी उतना ही सच है कि केवल सुरक्षा अभियानों की सफलता को अंतिम जीत नहीं माना जा सकता। स्थायी शांति तब स्थापित होगी,जब सुरक्षा के साथ विकास,विश्वास और सामाजिक न्याय भी समान गति से आगे बढ़ेंगे।

पिछले वर्षों में सुरक्षा बलों ने कई बड़े नक्सली नेताओं को गिरफ्तार किया, अनेक मुठभेड़ों में शीर्ष कैडर ढेर हुए और बड़ी संख्या में नक्सलियों ने मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया। सरकार का दावा है कि नक्सल संगठनों का प्रभाव क्षेत्र लगातार सिमट रहा है। जिन इलाकों में कभी प्रशासनिक अधिकारी जाने से बचते थे,वहां अब पुलिस कैंप स्थापित हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं और सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन शुरू हुआ है। यह बदलाव निश्चित रूप से सकारात्मक है और लंबे समय से हिंसा झेल रहे बस्तर के लिए उम्मीद की किरण भी है।

लेकिन यह भी याद रखना होगा कि नक्सलवाद केवल कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं था। इसके पीछे वर्षों का पिछड़ापन, विकास का अभाव, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी,रोजगार के सीमित अवसर,संचार व्यवस्था की कमजोरी और शासन-प्रशासन से दूरी जैसे अनेक कारण रहे हैं। यदि इन मूल कारणों का समाधान नहीं किया गया तो केवल सुरक्षा बलों की मौजूदगी से स्थायी शांति स्थापित करना कठिन होगा।

आज बस्तर के गांवों में सड़कें पहुंच रही हैं। मोबाइल नेटवर्क का विस्तार हुआ है। बिजली,पेयजल, स्कूल,छात्रावास और स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना,जल जीवन मिशन,आयुष्मान भारत,वन धन विकास केंद्र,पीएम जनमन योजना और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी धीरे-धीरे दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच रहा है। फिर भी यह स्वीकार करना होगा कि कई गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं से पूरी तरह नहीं जुड़ पाए हैं। जहां विकास आधा-अधूरा होगा,वहां असंतोष की संभावना बनी रहेगी।

बस्तर के भविष्य की सबसे बड़ी कुंजी वहां का युवा है। यदि युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा,तकनीकी प्रशिक्षण,प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी,खेल सुविधाएं और स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध होंगे तो हिंसा की विचारधारा स्वतः कमजोर पड़ेगी। आज भी अनेक युवा सेना,पुलिस,अर्धसैनिक बलों और अन्य सरकारी सेवाओं में चयनित होकर नई पहचान बना रहे हैं। यह सकारात्मक संकेत है,लेकिन इसे और व्यापक बनाने की आवश्यकता है। वन उपज आधारित उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण,हस्तशिल्प,बांस उद्योग,लघु वनोपज,पर्यटन और कृषि आधारित उद्यमों में बड़े निवेश से स्थानीय रोजगार के नए अवसर तैयार किए जा सकते हैं।

बस्तर केवल संघर्ष की भूमि नहीं है। यह भारत की समृद्ध आदिवासी संस्कृति,लोककला,हस्तशिल्प,जैव विविधता और प्राकृतिक पर्यटन का अनमोल केंद्र है। चित्रकोट जलप्रपात,तीरथगढ़,कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान,कुटुमसर गुफाएं, दंतेश्वरी मंदिर और यहां की पारंपरिक संस्कृति विश्व स्तर पर पहचान बनाने की क्षमता रखते हैं। यदि पर्यटन को योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जाए, स्थानीय समुदायों को उसका लाभ मिले और आधारभूत सुविधाओं का विस्तार हो,तो बस्तर आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर बन सकता है।

हालांकि विकास के नाम पर स्थानीय समाज की भावनाओं की अनदेखी भी नहीं होनी चाहिए। आदिवासी समुदाय की संस्कृति, परंपराएं,जल-जंगल-जमीन से जुड़ी उनकी जीवनशैली और संवैधानिक अधिकारों का सम्मान करना उतना ही आवश्यक है,जितना सड़क और पुल बनाना। विकास तभी सफल माना जाएगा, जब स्थानीय लोग स्वयं को उसका भागीदार महसूस करें, न कि केवल दर्शक।

सरकार के सामने एक और चुनौती है–सुरक्षा अभियानों में मिली सफलता को प्रशासनिक संवेदनशीलता में बदलना। गांवों में नियमित स्वास्थ्य सेवाएं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा,पारदर्शी प्रशासन,समय पर राशन,वन अधिकारों का प्रभावी क्रियान्वयन और सरकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के पहुंचे,तभी लोगों का भरोसा मजबूत होगा। विश्वास किसी भी सुरक्षा अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि होता है।

सुरक्षा बलों की भूमिका भी समय के साथ बदली है। अब केवल अभियान चलाना ही उनका उद्देश्य नहीं है। कई स्थानों पर पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल चिकित्सा शिविर,खेल प्रतियोगिताएं,करियर मार्गदर्शन,महिला जागरूकता अभियान और शिक्षा सहायता जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के साथ सकारात्मक संबंध स्थापित कर रहे हैं। यह बदलाव स्वागतयोग्य है,क्योंकि लोकतंत्र में जनता का विश्वास जीतना किसी भी सैन्य सफलता से अधिक महत्वपूर्ण होता है।

अब बस्तर को केवल नक्सल मानचित्र पर नहीं, बल्कि विकास के मानचित्र पर स्थापित करने का समय है। आने वाले वर्षों में यदि सरकार सुरक्षा, शिक्षा,स्वास्थ्य,रोजगार,पर्यटन,उद्योग और जनविश्वास–इन सभी क्षेत्रों में समान गति से कार्य करती है,तो बस्तर देश के सामने परिवर्तन का एक सफल मॉडल बन सकता है।

नक्सलवाद के विरुद्ध सबसे बड़ी जीत किसी मुठभेड़ में नहीं, बल्कि उस दिन होगी जब बस्तर का हर बच्चा स्कूल जाएगा,हर गांव सड़क और इंटरनेट से जुड़ेगा,हर युवा सम्मानजनक रोजगार पाएगा और हर परिवार बिना भय के अपना भविष्य तय कर सकेगा। बंदूकें शांति का रास्ता खोल सकती हैं,लेकिन उस रास्ते को स्थायी मंजिल तक केवल विकास,न्याय और विश्वास ही पहुंचा सकते हैं।

अमर शहीद-ए-आज़म उधम सिंह

प्रो.शामलाल कौशल
रोहतक,हरियाणा

अंग्रेजी गुलामी की बेड़ियों से देश को आजाद कराने के लिए सभी जातियों तथा धर्मों के लोगों ने हंसते हंसते कुर्बानियां दी, जेल गए,काले पानी की सजा भुगती,गोलियां खाई और हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा। इस शुभ काम को अंजाम तक पहुंचाने वाले संयुक्त पंजाब के कुछ गिने-चुने शहीदों में शहीद-ए-आजम भगत सिंह,लाला लाजपत राय,उधम सिंह,सुखदेव,बाबा गुरदित सिंह,सोहन सिंह,करतार सिंह सराभा,मदनलाल ढींगरा आदि का नाम लिया जा सकता है।

परंतु इन नामों में जिस अमर शहीद का हम जिक्र करने जा रहे हैं उनका नाम है शहीद-ए-आजम उधम सिंह। उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर,1899 को पंजाब के जिला संगरूर की तहसील, सुनाम के एक गांव में एक सिख परिवार में हुआ था। इन के बचपन का नाम शेर सिंह था। उनके पिता,टहल सिंह अमृतसर के गांव के पास के रेलवे फाटक पर चौकीदार थे। उनकी माता का नाम नारायण कौर था। अभी उधम सिंह लगभग 7 साल की उम्र के होंगे कि उनके माता पिता का देहांत हो गया। और उनका पालन पोषण अमृतसर के खालसा अनाथालय में हुआ। 13 अप्रैल, 1919 को जब जलियां वाले बाग में इकट्ठे हुए स्वतंत्रता सेनानी पुरुष,स्त्रियों तथा बच्चों पर जालिम गवर्नर जनरल डायर के आदेश के अनुसार बिना चेतावनी के लगभग 1000 निर्दोष लोगों को गोलियों से भून दिया गया तथा हजारों स्वतंत्रता सेनानियों को जख्मी कर दिया गया तो सारे देश में जनरल डायर तथा अंग्रेजो के खिलाफ नफरत तथा गुस्से की आग जल उठी। अनाथालय की तरफ से उधम सिंह तथा अन्य लोगों को जलिया वाले बाग में जख्मी लोगों को पानी पिलाने तथा उनकी मरहम पट्टी करने के लिए भेजा गया। उधम सिंह ने वहां पर हजारों शहीद स्वतंत्रता सेनानियों तथा जख्मी लोगों को गोलियों की पीड़ा से कराहते हुए देखा तो उनके मन में जनरल डायर तथा अंग्रेजों के खिलाफ ज्वालामुखी फट गया और उधम सिंह ने जनरल डायर से इसका बदला लेने का निश्चय कर लिया। उधम

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

सिंह का नारा था...इंग्लैंड मुर्दाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद...बाद में उधम सिंह गदर पार्टी के सदस्य बन गए। वह सरदार भगत सिंह के विचारों से बहुत प्रभावित हुए इस महान स्वतंत्रता सेनानी ने नाम बदल बदल कर अफ्रीका,अमेरिका, ब्राजील आदि देशों का भ्रमण किया। भगत सिंह ने इनको भारत वापस लौट आने के लिए कहा। भारत आते समय यह अपने साथ बिना लाइसेंस के 25 रिवाल्वर,गोला बारूद आदि ले आए जिसके कारण इन्हें 4 साल की जेल की सजा हो गई। जेल से छूटने के बाद पहले यह कश्मीर और बाद में जर्मनी चले गए और अंततःजनरल डायर को मारने के मकसद के लिए लंदन पहुंच गए और सही समय का इंतजार करने लगे। 21 साल तक इंतजार करने के बाद एक दिन 13 मार्च, 1940 को रॉयल एशियन सोसायटी लंदन के हाल में जब जनरल डायर संबोधन के लिए आए तो उधम सिंह ने जनरल डायर पर 5,6 गोलियां दाग दी जिससे जनरल डायर की उसी समय मृत्यु हो गई। इस तरह उधम सिंह ने जलियां वाले बाग के हत्याकांड का सार्वजनिक तौर पर जनरल डायर को मारकर बदला ले लिया और दुनिया को बता दिया कि भारतवासी स्वतंत्रता सेनानियों के हत्यारों को छोड़ते नहीं और अपने काम को अंजाम देने के बाद उधम सिंह अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागे नहीं। इसके बाद उधम सिंह को पुलिस ने पकड़ लिया और उन पर जनरल डायर की हत्या का मुकदमा चला तथा 31 जुलाई, 1940 को लंदन की एक जेल में उनको फांसी दे दी गई। उधम सिंह को फांसी दिए जाने के बाद भारत के स्वतंत्रता सेनानियों तथा देशवासियों में अंग्रेजो के खिलाफ और भी नफरत तथा गुस्से की आग भड़क उठी और उसके 7 साल के बाद देश को अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा मिला। इसके बाद 31 जुलाई, 1974 को इस महान शहीद के शरीर के पुण्य अवशेषों को सम्मान के साथ भारत लाया गया और इनके पैतृक गांव,सुनाम में शहीद को सम्मानजनक श्रद्धांजलि स्वरूप इनकी समाधि बना दी गई। हर साल सुनाम में समाधि पर सम्मानजनक ढंग से श्रद्धांजलि दी जाती है। इस महान शहीद के सम्मान सूचक के तौर पर अमृतसर में जलियां वाले बाग के पास एक म्यूजियम बनाया गया है! इन्हें श्रद्धांजलि तथा सम्मान देने के लिए छत्तीसगढ़ में उधम सिंह नगर नाम का एक शहर भी बसाया गया है। जब कभी भी जनरल डायर द्वारा 13 अप्रैल, 1919 को जलियां वाले बाग हत्याकांड का जिक्र आएगा,उसे मौत की नींद सुलाने वाले शहीद उधम सिंह का नाम भी जरूर आएगा! शहीद उधम सिंह जिंदाबाद।

शहीदों की चिताओं पर
लगेंगे हर बरस मेले।
वतन पर जान देने वालों का
यही बाकी निशां होगा।

जनता के बेवकूफ समझने वाले नेताओं के हिस्से में आती है सिर्फ सियासी दुर्दशा

अजय कुमार
लखनऊ,उत्तरप्रदेश

बात हाल-फिलहाल की है,जब भारत के दिल और देश की राजधानी दिल्ली का जंतर-मंतर कॉंकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन की हेडलाइनों की तपिश से उबल रहा था। पूरे देश में इस आंदोलन को लेकर चर्चा गरम थी। चाय की एक दुकान पर टंगे टेलीविजन स्क्रीन पर तीन-चार नेता एक-दूसरे पर चिल्ला रहे थे। बहस का विषय देश का विकास,युवाओं की नौकरियां,महिलाओं की सुरक्षा या किसानों की बदहाली नहीं था,बल्कि एक मामूली स्थानीय घटना को लेकर शुरू हुआ ऐसा विवाद था, जिसे मजहबी और सियासी रंग दे दिया गया था। बहस में शामिल एक युवा नेता पूरी ताकत से चिल्लाकर अपने से दुगनी उम्र के विरोधी नेता को सरेआम भ्रष्टाचारी और अपराधियों का सरपरस्त घोषित कर रहा था। उसके पास न तो कोई अदालती सबूत था और न ही कोई पुख्ता दस्तावेज,लेकिन उसकी आवाज की कड़वाहट और अपशब्दों की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि एंकर भी मूकदर्शक बना हुआ था। चाय की चुस्की लेते हुए वहां खड़े एक बुजुर्ग ने गहरी सांस छोड़कर पास बैठे नौजवान से कहा कि आजकल जो जितना घटिया और तीखा बोलता है,उसे उतना ही बड़ा और जुझारू नेता मान लिया जाता है,सियासी तजुर्बे और मर्यादा की तो जैसे अब कोई कीमत ही नहीं बची है।

यह दृश्य आज देश की समकालीन राजनीति का एक ऐसा कड़वा सच बन चुका है,जहां राजनीति हर समय 24 घंटे और 365 दिन चरम पर रहती है। चुनाव खत्म हो जाते हैं, सरकारें बन जाती हैं,लेकिन चुनावी मोर्चेबंदी और नफरत का माहौल कभी शांत नहीं होता। राजनीति का स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है और सार्वजनिक विमर्श से वे मुद्दे पूरी तरह गायब हो चुके हैं,जो सीधे तौर पर आम नागरिक के जीवन को प्रभावित करते हैं। आज देश के युवाओं की तरक्की,रोजगार के नए अवसरों का निर्माण, महिलाओं का सम्मान और उनकी वास्तविक सुरक्षा, किसानों की आय दोगुनी करना,मजदूरों को उनका हक दिलाना और कानून व्यवस्था को मजबूत करके अपराधियों पर शिकंजा कसना जैसे बुनियादी विषय राजनीतिक दलों के घोषणापत्रों की धूल फांक रहे हैं। नेताओं की चिंता अब देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने की कम और सोशल मीडिया पर अपनी रील्स और बयानों को वायरल करवाकर सुर्खियां बटोरने की ज्यादा हो गई है। अपनी राजनीति चमकाने के लिए बेहद छोटी और स्थानीय घटनाओं

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

को तिल का ताड़ बनाकर पेश करना कुछ सियासी सूरमाओं का रोज का काम बन गया है।

इस गिरते स्तर का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि अब बिना किसी जांच या सबूत के किसी भी सम्मानित व्यक्ति या विरोधी पर सीधे भ्रष्टाचार, बलात्कारियों को संरक्षण देने या चंदा चोरी जैसे गंभीर आरोप लगा दिए जाते हैं। टीवी कैमरों के सामने आकर बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं,प्रेस कॉन्फ्रेंस में सनसनी फैलाई जाती है,लेकिन जब अदालत में सबूत पेश करने या जिम्मेदारी लेने का वक्त आता है, तो यही नेता अपनी बात से पलट जाते हैं या फिर विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। जिम्मेदारी से भाग जाना और झूठे आरोपों के पीछे छिप जाना आज के कई राजनेताओं का स्थायी चरित्र बन चुका है। हद तो तब हो जाती है,जब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कुछ नेता देश की तुलना पड़ोसी मुल्कों से करने लगते हैं। कोई भारत को नेपाल जैसी अस्थिरता की तरफ धकेलने की बात करता है,तो कोई खुलेआम धमकी देता है कि अगर उनकी बातें न मानी गईं तो देश के हालात बांग्लादेश जैसे हो जाएंगे,जहां तख्तापलट और हिंसा का तांडव देखने को मिला था। ऐसी गैर-जिम्मेदाराना बयानबाजी करते वक्त वे भूल जाते हैं कि वे उसी लोकतंत्र की थाली में छेद कर रहे हैं,जिसने उन्हें पहचान और पावर दी है।

इस पूरे तमाशे में सबसे बड़ा सहारा संविधान को बनाया जाता है। हर छोटा-बड़ा नेता हाथ में संविधान की किताब लेकर घूमता दिखाई देता है और खुद को उसका सबसे बड़ा रक्षक घोषित करता है। लेकिन विडंबना देखिए कि उसी संविधान की दुहाई देकर रोज लोकतांत्रिक संस्थाओं का अपमान किया जाता है, न्यायपालिका पर सवाल उठाए जाते हैं और कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। संविधान को ढाल बनाकर देश के ताने-बाने को तार-तार करने का यह खेल अब जनता भी समझने लगी है। इसी राजनीति का एक और दुःखद और घिनौना पहलू यह है कि प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्ष दिखने की होड़ में किसी न किसी बहाने से सनातन परंपराओं और हिंदुओं को गाली देना आज एक फैशन और नया रिवाज बन गया है। बहुसंख्यक समाज की आस्था, उनके त्योहारों और उनकी संस्कृति पर अभद्र टिप्पणियां करके कुछ राजनीतिक दल एक खास वोट बैंक को साधने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि सनातन को नीचा दिखाकर वे खुद को आधुनिक और मसीहा साबित कर देंगे,लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि इस देश की आत्मा सर्वधर्म समभाव में बसती है और किसी एक धर्म को लगातार निशाना बनाना समाज में केवल नफरत का जहर ही घोलता है।

इन नेताओं की सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि ये जनता को बेवकूफ समझते हैं। वातानुकूलित कमरों में बैठकर सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के भरोसे राजनीति करने वाले इन सियासी दलों को लगता है कि वे जनता से बहुत ज्यादा होशियार और काबिल हैं। वे सोचते हैं कि वे जो भी नैरेटिव या झूठ परोसेंगे,जनता उसे सच मानकर आंखें बंद कर लेगी। वे जनता की खामोशी को उनकी नासमझी मान बैठते हैं। लेकिन भारतीय लोकतंत्र का इतिहास गवाह है कि जब-जब नेताओं का अहंकार सातवें आसमान पर पहुंचा है,तब-तब इसी देश की साधारण और गरीब जनता ने अपने वोट की ताकत से बड़े-बड़े सूरमाओं के सिंहासन को मिट्टी में मिला दिया है। जनता नेताओं की हर चाल, उनके हर खोखले वादे,उनके झूठे आरोपों और उनकी नफरत भरी बयानबाजी को बहुत बारीकी से देखती है। जब चुनाव का समय आता है, तो वह बिना कोई शोर मचाए ईवीएम का बटन दबाकर इन घमंडी और खुद को जरूरत से ज्यादा चालाक समझने वाले नेताओं को उनकी सही जगह दिखा देती है।

हाल के वर्षों में ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं, जहां जनता ने उन दलों और नेताओं को बार-बार ठुकराया है, जो केवल नकारात्मकता, झूठे आरोपों और बहुसंख्यक समाज को गाली देने की राजनीति पर निर्भर थे। जिन राज्यों में नेताओं ने विकास के काम ठप्प करके केवल जातिगत नफरत और तुष्टिकरण का खेल खेला,वहां की जनता ने उन्हें सत्ता के गलियारों से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जिन नेताओं ने बिना सबूत के कीचड़ उछालने को ही अपना मुख्य पेशा बना लिया था,उन्हें जनता ने चुनावों में करारी शिकस्त देकर यह संदेश दिया कि देश को गालीबाज नहीं,बल्कि काम करने वाले जनसेवक चाहिए। लेकिन इस लोकतांत्रिक थप्पड़ के बाद भी इन नेताओं के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। चुनाव हारने के बाद अपनी गलतियों को सुधारने और आत्ममंथन करने के बजाय, इन सियासी दलों का हो-हल्ला मचाने का सिलसिला और तेज हो जाता है। वे अपनी हार का ठीकरा कभी ईवीएम पर फोड़ते हैं, कभी चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हैं,तो कभी जनता के विवेक पर ही सवाल उठाने लगते हैं। वे यह मानने को तैयार ही नहीं होते कि जनता ने उनके खोखलेपन और उनकी नफरत की राजनीति को खारिज कर दिया है।

संसद से लेकर सड़क तक इनका यह हंगामा और शोर-शराबा थपने का नाम नहीं लेता,क्योंकि इनका मकसद देश का सुधार करना नहीं,बल्कि किसी भी तरह सत्ता हथियाना या फिर चर्चा में बने रहना है। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि उनके इस गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार से देश की छवि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खराब होती है या युवा पीढ़ी के मन में राजनीति के प्रति पूरी तरह से वितृष्णा पैदा हो रही है। आज का जागरूक युवा जब इन नेताओं को संसद में कागज फाड़ते,आसन के सामने चिल्लाते और घटिया स्तर की भाषा का इस्तेमाल करते देखता है,तो उसका लोकतंत्र के इस पूरे ढांचे से भरोसा डगमगाने लगता है। राजनीति,जो कभी देश सेवा और समाज सुधार का सबसे पवित्र माध्यम मानी जाती थी,उसे इन स्वार्थी और अहंकारी नेताओं ने व्यक्तिगत दुश्मनी साधने और अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने का अखाड़ा बना दिया है।

आम जनता के दिलों में देश की इस राजनीतिक स्थिति को लेकर चिंता साफ देखी जा सकती थी। ये नेता चाहे जितना भी हो-हल्ला मचा लें,चाहे जितना भी खुद को जनता से ज्यादा होशियार समझ लें, आखिरी फैसला इसी देश की मिट्टी और यहां के लोगों को करना है। जो दल देश के विकास,युवाओं के रोजगार और महिलाओं के सम्मान की चिंता छोड़कर केवल विभाजन और अपशब्दों का सहारा लेगा, उसे यह जनता बार-बार और हर बार ठुकराती रहेगी। शोर मचाने वाले नेता कुछ समय के लिए सुर्खियां तो पा सकते हैं,लेकिन वे कभी जनता के दिलों में जगह नहीं बना सकते। भारतीय लोकतंत्र की असली ताकत इसकी समझदार जनता है, जो समय आने पर हर अहंकारी और झूठे राजनेता का भ्रम बड़ी खामोशी और बेमुरव्वत तरीके से तोड़ देती है, और यही इस देश के भविष्य की सबसे बड़ी उम्मीद भी है।

युवाओं के हाथ में अराजकता का झंडा थमाने की विपक्षी रणनीति

संजय सक्सेना
लखनऊ,उत्तरप्रदेश

भारतीय राजनीति में लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शनों का एक गरिमामय इतिहास रहा है। संविधान ने नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों को रखने और विरोध दर्ज कराने का मौलिक अधिकार दिया है। लेकिन बीते कुछ वर्षों में देश की राजनीति में एक खतरनाक प्रवृत्ति देखने को मिली है,जहाँ लोकतांत्रिक आंदोलन की आड़ में उपद्रवी और अराजक तत्व हिंसा फैलाते हैं और राजनीतिक दल अपने संकीर्ण स्वार्थों के लिए उन दंगाइयों-उपद्रवियों को कभी मासूम जनता, मासूम छात्र और युवा या अन्नदाता बताकर देश में अराजकता फैलाने और लोगों को भड़काने की साजिश में जुट जाते हैं। हाल ही में जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शनों और उपद्रव के दौरान भी यही पटकथा दोहराई गई। उपद्रवियों और हिंसा फैलाने वालों को छात्रों का चोला पहनाकर पूरे देश के युवाओं की संवेदनाओं से खेलने का प्रयास किया जा रहा है। यह पहला अवसर नहीं है;इससे पूर्व किसान आंदोलन, नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) विरोधी प्रदर्शन,और एसआईआर आंदोलन के दौरान भी विपक्ष ने अराजकता फैलाने वालों को ढाल बनाकर अपने राजनीतिक मंसूबों को साधने का प्रयास किया था। इसकी जड़ में जाया जाये तो पता चलता है कि जब-जब देश में बड़े कानून बने या प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण की दिशा में कदम उठाए गए,तब-तब एक खास राजनीतिक तंत्र ने उन सुधारों का रचनात्मक विरोध करने के बजाय सड़कों पर हिंसा और व्यवधान उत्पन्न करने वाली शक्तियों को संरक्षण दिया। सीएए विरोधी आंदोलन, नागरिकता देने वाले कानून को नागरिकता छीनने वाला भ्रम बनाकर देश के विभिन्न हिस्सों में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। हिंसा में लिप्त असामाजिक तत्वों के पक्ष में राजनीतिक बयानबाजी की गई।

इसी तरह से किसानों के नाम पर दिल्ली की सीमाओं को महीनों तक घेरा गया, जिससे आम नागरिकों और देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ। 26 जनवरी को लाल किले पर हुई ऐतिहासिक हिंसा और राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के दोषियों का बचाव करने में भी राजनीतिक दलों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जंतर-मंतर पर हालिया प्रदर्शनों के दौरान जब स्थिति बिगड़ी और उपद्रवियों द्वारा सुरक्षा बलों एवं आम जनजीवन को निशाना बनाया गया,तब पुनः वही घिसा-पिटा वृत्तांत गढ़ा गया कि सरकार निर्दोष छात्रों पर अत्याचार कर रही है।उधर, न्यायपालिका ने बार-बार स्पष्ट किया है कि विरोध प्रदर्शन का अधिकार कानून हाथ में लेने या हिंसा फैलाने का लाइसेंस नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई मील के पत्थर साबित होने वाले फैसलों में यह सिद्धांत तय किया है। आंदोलन या

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

विरोध के नाम पर सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वाले, कानून-व्यवस्था को भंग करने वाले और सार्वजनिक हिंसा में शामिल पूर्व के अपराधियों एवं उपद्रवियों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को राजनीतिक दबाव में वापस नहीं लिया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय का यह रुख स्पष्ट करता है कि कानून की नजर में उपद्रवी केवल उपद्रवी होता है,चाहे वह खुद को छात्र कहे या आंदोलनकारी।

बहरहाल,अदालत के इस स्पष्ट और सख्त रुख के बावजूद,आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज और अन्य नेताओं ने अदालती प्रक्रिया और फैसलों पर राजनीतिक बयानबाजी की। न्यायपालिका द्वारा आपराधिक मामलों को वापस न लेने के फैसले के खिलाफ जिस प्रकार की तीखी भाषा का प्रयोग किया गया, उसने न्यायिक मर्यादाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अदालत को एक तरह से राजनीतिक चुनौती देना या सार्वजनिक रूप से दबाने का प्रयास करना न्याय तंत्र की निष्पक्षता पर सीधा हमला है। विपक्ष के वृत्तांत की सबसे बड़ी कमजोरी उसका दोहरा रवैया और चयनात्मक संवेदनशीलता है।बात पैलेट गन के इस्तेमाल की भी जरूरत है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी संसद से लेकर सड़कों तक पेलेट गन की एक घटना को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचाए हुए हैं और संसद की कार्यवाही नहीं चलने दे रहे हैं। निस्संदेह किसी भी नागरिक या छात्र का घायल होना दुखद है और उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन इस एक घटना को राजनीतिक ढाल बनाकर संसद की कार्यवाही को ठप करना, देश के करोड़ों रुपये और विधायी समय को बर्बाद करना कहाँ तक न्यायसंगत है? दूसरी तरफ, प्रतियोगी परीक्षाओं के तनाव, कोचिंग संस्थानों की लापरवाही और प्रशासनिक कमियों के चलते जब हाल ही में लगभग 21 छात्र-छात्राओं की अकाल मृत्यु (आत्महत्या और दुर्घटनाओं) हुई,तो उस गंभीर त्रासदी पर विपक्ष की ओर से वैसी संवेदनशीलता नहीं दिखाई गई।

पैलेट गन की घटना पर विपक्ष ने संसद की कार्यवाही बाधित की, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीं और आक्रामक बयान दिए,जबकि 21 छात्रों की मृत्यु पर सीमित या नाममात्र की बयानबाजी देखने को मिली। पेलेट गन की घटना में नेता पीड़ित के घर पहुँचे या मीडिया में उनके साथ दिखाई दिए,लेकिन 21 मृतक छात्र-छात्राओं के मामले में किसी प्रमुख विपक्षी नेता का परिवारों से मिलने पहुँचना भी आवश्यक नहीं समझा गया। जहाँ एक घटना में सरकार विरोधी माहौल बनाने का प्रयास हुआ,वहीं दूसरी घटना में राजनीतिक लाभ न दिखने के कारण उपेक्षा दिखाई दी। चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी, किसी भी बड़े नेता ने उन 21 मृतक छात्र-छात्राओं के पीड़ित परिवारों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनका दर्द बाँटना जरूरी नहीं समझा। यह विरोधाभास साफ दर्शाता है कि विपक्ष की संवेदनाएँ छात्रों के भविष्य या उनके जीवन से नहीं, बल्कि इस बात से तय होती हैं कि किस घटना से सरकार पर राजनीतिक हमला बोला जा सकता है।

सब जानते हैं कि युवा किसी भी देश की रीढ़ होते हैं। उनकी ऊर्जा,उनका आक्रोश और उनकी आकांक्षाएँ देश के निर्माण में काम आनी चाहिए। लेकिन जब राजनीतिक दल अपने स्वार्थों के लिए युवाओं के हाथों में किताबों के बजाय अराजकता का झंडा थमाने की कोशिश करते हैं, तो इसका नुकसान पूरे समाज को उठाना पड़ता है। जब आपराधिक छवि के लोग या हिंसा फैलाने वाले उपद्रवी छात्रों के भेष में शामिल होते हैं, तो वास्तविक और जायज मांगों के लिए लड़ रहे सच्चे छात्रों की आवाज भी दब जाती है। हर मुद्दे पर संसद को ठप करना देश के लोकतांत्रिक ढाँचे को कमजोर करता है। उपद्रवियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग करना भविष्य के अपराधियों को यह संदेश देता है कि वे हिंसा करके भी राजनीतिक संरक्षण पा सकते हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सर्वोपरि है, लेकिन हिंसा और अराजकता की आड़ में देश की व्यवस्था को बंधक बनाना कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि हिंसा के दोषियों को सजा मिलनी ही चाहिए।

विपक्ष को यह समझना होगा कि हर विरोध प्रदर्शन को राजनीतिक हथियार बनाकर देश के युवाओं को भड़काने की नीति दीर्घकालिक रूप से देशहित और स्वयं उनके राजनीतिक भविष्य के लिए घातक है। पेलेट गन की घटना पर आक्रामक होकर संसद रोकना और दूसरी तरफ दर्जनों मृत छात्रों के परिवारों की उपेक्षा करना विपक्ष की संवेदनहीनता और दोहरे चरित्र को उजागर करता है। देश का युवा आज जागरूक है;वह समझता है कि कौन उसके भविष्य की बात कर रहा है और कौन उसे केवल राजनीतिक मोहरा बना रहा है। विपक्ष को लगता है कि वह अगले साल पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में इसका फायदा उठा लेगा तो यह इतना सहज नहीं है क्योंकि जनता सब जानती है।

निश्चल संवेदना

डॉ.राजीव डोगरा
कांगड़ा हिमाचल प्रदेश

बदलते वक्त के साथ
बहुत कुछ बदलता देखा
मित्र को शत्रु बनते
शत्रु को मित्र बनते देखा।
जानता भी नहीं था जिनको
उनको अपना बनते देखा
और जानता था जिनको
उनको पराया होते देखा।
भागता रहा हमेशा ही
अपनों की तलाश में
खोजता रहा भावनाओं के द्वार
हर किसी के हृदय में।
अन्वेषण करता रहा
विचारों को समझने वालों की
खोजता रहा मन के मीतों को
जो समझ जाए मेरे हृदय की
हर निश्चल संवेदनाओं को।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

सम्पादक

नाबालिग आदिवासी बालिका दुष्कर्म मामला...गिरफ्तारी में देरी पर भाजपा का हल्लाबोल

एसपी कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन,पीड़ित परिवार पर दबाव बनाने वालों पर भी कार्रवाई की मांग

भाजपा का आरोप : प्रभाव के चलते गिरफ्तारी में देरी,न्याय प्रक्रिया प्रभावित करने की हो रही कोशिश

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,31 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

सरगुजा जिले के चर्चित नाबालिग आदिवासी बालिका दुष्कर्म मामले में मुख्य आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने पर शनिवार को सियासी पारा चढ़ गया। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा और महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर जोरदार विरोध दर्ज कराया और आरोपी तरुण जायसवाल की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए एसपी को ज्ञापन सौंपा। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि आरोपी की गिरफ्तारी में हो रही देरी से पीड़ित परिवार में भय का माहौल है, जबकि प्रभावशाली लोगों द्वारा मामले को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया के मार्गदर्शन में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि यह मामला केवल एक आपराधिक घटना नहीं बल्कि आदिवासी समाज की अस्मिता और बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय है। ऐसे मामलों में यदि आरोपी खुलेआम घूमता रहे और पुलिस समय पर कार्रवाई नहीं करे तो इससे कानून व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया पर लोगों का विश्वास कमजोर होता है।

समझौते के लिए बनाया जा रहा दबाव : भाजपा जिला महामंत्री विनोद हर्ष ने आरोप लगाया कि आरोपी पक्ष के परिजन लगातार पीड़ित परिवार पर समझौते का दबाव बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के परसा मंडल अध्यक्ष एवं पूर्व सरपंच विवेक पैकरा तथा उनके परिवार के कुछ सदस्यों द्वारा कथित रूप से आर्थिक प्रलोभन देकर मामले को दबाने का प्रयास किया गया। उन्होंने मांग की कि इन आरोपों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध भी कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि यदि प्रभावशाली लोगों द्वारा न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करने के प्रयासों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो इससे आम लोगों का न्याय व्यवस्था से विश्वास उठ जाएगा।

आदिवासी समाज अपनी बेटियों के सम्मान पर समझौता नहीं करेगा

अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष बिंदेश्वरी पैकरा ने कहा कि आदिवासी समाज अपनी बेटियों की सुरक्षा और सम्मान के प्रश्न पर किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर मामले को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। यदि उसकी जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो पीड़िता,उसके परिजनों और अन्य गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि यह केवल एक परिवार का मामला नहीं बल्कि पूरे आदिवासी समाज के सम्मान और न्याय का प्रश्न है।

भफौली पहुंचा था महिला मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल

भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष शुभांगी बिहाड़े ने बताया कि हाल ही में महिला मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल ग्राम भफौली पहुंचकर पीड़िता और उसके परिजनों से मिला था। उन्होंने कहा कि परिवार अभी भी भय और मानसिक तनाव के दौर से गुजर रहा है तथा उसे न्याय मिलने की उम्मीद पुलिस की निष्पक्ष कार्रवाई पर टिकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा महिला मोर्चा इस कठिन समय में पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है और दोषियों को सजा दिलाने के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगा। महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध किसी भी सभ्य समाज के लिए अस्वीकार्य हैं और ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई आवश्यक है।

भाजपा ने एसपी से कीं ये प्रमुख मांगें...

- मुख्य आरोपी तरुण जायसवाल को तत्काल गिरफ्तार किया जाए।
- पीड़ित परिवार को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए।
- मामले की निष्पक्ष एवं समयबद्ध विवेचना पूरी की जाए।
- समझौते के लिए दबाव,धमकी या आर्थिक प्रलोभन देने वालों के विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई की जाए।

बड़ी संख्या में पहुंचे भाजपा पदाधिकारी

ज्ञापन सौंपने के दौरान महिला मोर्चा प्रदेश महामंत्री फुलेश्वरी सिंह, भाजपा जिला महामंत्री अरुणा सिंह, निलेश सिंह, सत्यम साहू, जन्मेजय मिश्रा, रूपेश दुबे, रविकांत उरांव, प्रियंका चौबे, सरस्वती यादव, अनीश सिंह, अविनाश मंडल सहित भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा, महिला मोर्चा और पार्टी के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

दो बड़े मामलों में पुलिस पर बढ़ा दबाव गिरफ्तारी को लेकर सड़क पर उतरे लोग

दुष्कर्म मामले में कोतवाली का घेराव,करोड़ की उठाईगिरी पर सीतापुर में पांच घंटे चक्काजाम

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,31 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

जिले के दो चर्चित आपराधिक मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से पुलिस पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अंबिकापुर में नाबालिग आदिवासी बालिका से दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों और परिजनों ने कोतवाली का घेराव कर प्रदर्शन किया,वहीं भाजपा महिला मोर्चा ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। दूसरी ओर सीतापुर में एक करोड़ रुपए के जेवरात की उठाईगिरी का खुलासा नहीं होने से नाराज व्यापारियों ने बाजार बंद कर पांच घंटे तक नेशनल हाईवे पर चक्काजाम किया। दोनों मामलों में लोगों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए जल्द गिरफ्तारी की मांग की।

दुष्कर्म के आरोपी पर 5 हजार का इनाम,फिर भी गिरफ्त से दूर : ग्रामीण क्षेत्र में 20 जुलाई को नाबालिग आदिवासी बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपी तरुण जायसवाल अब तक फरार है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी और सूचना देने वाले के लिए 5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है, लेकिन सफलता नहीं मिली। इससे नाराज परिजन और ग्रामीण गुरुवार शाम पूर्व पार्षद सतीश बारी के नेतृत्व में कोतवाली पहुंचे और प्रदर्शन कर आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। शुक्रवार को भाजपा महिला मोर्चा ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की। महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष सुभंगी बिहाड़े ने कहा कि पीड़िता और उसका परिवार भय और सदमे में है। ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई जरूरी है।

करोड़ की उठाईगिरी से व्यापारियों में नाराजगी : सीतापुर में 26 जुलाई को ज्वेलरी व्यवसायी की स्कूटी से करीब एक करोड़ रुपए के जेवरात से भरा बैग चोरी होने के मामले में भी अब तक आरोपियों का सुराग नहीं मिला है। इससे नाराज व्यापारियों ने शुक्रवार को बाजार बंद रखकर कारगिल चौक पर चक्काजाम किया। उनका कहना है कि घटना सीसीटीवी में कैद होने के बावजूद पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच सकी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमोलक सिंह ढिल्लों ने व्यापारियों से चर्चा कर मामले के खुलासे के लिए एक सप्ताह का समय मांगा। आश्वासन के बाद शाम पांच बजे चक्काजाम समाप्त कर दिया गया। प्रदर्शन के दौरान एंबुलेंस को निर्बाध आवाजाही की अनुमति दी गई, जबकि अन्य वाहनों को वैकल्पिक मार्ग से निकाला गया।

नाबालिगों की ड्राइविंग रोकने सरगुजा पुलिस का विशेष अभियान,स्कूलों में पहुंचकर किया जा रहा जागरूक

बिना लाइसेंस वाहन चलाने वाले छात्रों के अभिभावकों की होगी काउंसलिंग,नियमों की अनदेखी पर होगी वैधानिक कार्रवाई

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,31 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

सरगुजा पुलिस ने नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए जिलेभर में विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया है। डीआईजी एवं एसएसपी राजेश अग्रवाल के निर्देशन में थाना, चौकी एवं यातायात पुलिस की टीमें स्कूलों में पहुंचकर छात्र-छात्राओं को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों की जानकारी दे रही हैं। अभियान का उद्देश्य नाबालिगों को सड़क दुर्घटनाओं से बचाना और सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करना है। अभियान के तहत विभिन्न शिक्षण संस्थानों में छात्र-छात्राओं को बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाहन नहीं चलाने, हेलमेट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने तथा यातायात नियमों का पालन करने की समझाइश दी जा रही है। साथ ही उन्हें स्कूल आने-जाने के लिए अधिकृत स्कूल वाहन या परिजनों के साथ यात्रा करने की सलाह दी गई। पुलिस ने जिले के सभी विद्यालयों के प्राचार्यों और प्रधान पाठकों से भी अपील की है कि बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस दोपहिया वाहन से आने वाले छात्रों को विद्यालय आने की अनुमति न दें। यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पाया जाता है तो उसके अभिभावकों को बुलाकर काउंसलिंग की जाएगी। सुधार नहीं होने की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम के तहत चलानी एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

अभियान के दौरान पुलिस टीम ने वाहन लेकर स्कूल पहुंचे छात्रों से ड्राइविंग लाइसेंस और हेलमेट के संबंध में पूछताछ भी की तथा उन्हें नियमों के उल्लंघन पर होने वाली कार्रवाई से अवगत कराया। सरगुजा पुलिस ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने नाबालिग बच्चों को किसी भी परिस्थिति में वाहन चलाने के लिए न दें और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करें। पुलिस का यह जागरूकता अभियान आगामी दिनों में भी लगातार जारी रहेगा।

टांगी से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को 7 साल की सजा

विशेष न्यायालय ने 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,31 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

अनुसूचित जनजाति के एक व्यक्ति पर टांगी से जानलेवा हमला करने के मामले में विशेष न्यायालय (अत्याचार निवारण) ने आरोपी को 7 वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। प्रकरण के अनुसार, सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम सरगा स्कूलपारा निवासी सकुन्दर अगरिया (40) अपनी बेटी को गांव के ही संजय कुजूर द्वारा पत्नी के रूप में साथ रखने से नाराज था। 4 जुलाई 2023 की सुबह करीब 10 बजे वह टांगी लेकर संजय कुजूर के घर पहुंचा और गाली-गलौज करने लगा। इसी दौरान संजय के रिश्तेदार नरेंद्र कुजूर ने उसे गाली देने से मना किया। इस पर सकुन्दर ने नरेंद्र पर टांगी से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद नरेंद्र की पत्नी दिनो कुजूर ने सीतापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय (अत्याचार निवारण), अंबिकापुर में हुई। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए विशेष न्यायाधीश अतुल श्रीवास्तव ने सकुन्दर अगरिया को 7 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

जमीन पर सोने के दौरान सांप ने डंसा,वृद्ध की मौत

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,31 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

ग्राम पचावल में जमीन पर सोने के दौरान एक वृद्ध सर्पदंश का शिकार हो गया। परिजन उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया था। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार परशु राम उम्र 61 वर्ष बलरामपुर जिले के ग्राम पचावल का रहने वाला था। वह 28 जुलाई की रात को खाना खाने के बाद जमीन में बिस्तर लगाकर घर में सो रहा था। रात करीब 1 बजे उसे करैत सांप ने डंस लिया। इसकी जानकारी वह अपने बेटे को दी। बेटा ने जाकर देखा तो कमरे में करैत सांप था। जिसे मारकर कढ़ाई से ढंक दिए और सुबह उसे इलाज के लिए बलरामपुर अस्पताल में ले गए। यहां प्राथमिक उचार के बाद चिकित्सक ने उसे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। यहां इलाज के दौरान 30 जुलाई को उसकी मौत हो गई।

गलत सरपंच की गिरफ्तारी पर बवाल : रिकॉर्ड की चूक या प्रशासनिक लापरवाही?

चिताबहार के गबन मामले में सरईटिकरा के सरपंच को गिरफ्तार कराने का आरोप,कांग्रेस ने सीईओ को हटाने और लिखित माफी की उठाई मांग

पांच साल पुराने मामले में कार्रवाई, लेकिन आरोपी की जगह दूसरे गांव के सरपंच पर गिरी गाज,एसडीएम कोर्ट में जमानत लेने से भी किया इनकार

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,31 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

अम्बिकापुर जनपद पंचायत में अभिलेखों की कथित लापरवाही अब बड़ा प्रशासनिक विवाद बन गई है। वर्ष 2020-21 में ग्राम चिताबहार में सामुदायिक शौचालय निर्माण में कथित 1.75 लाख रुपये की अनियमितता के मामले में जिस व्यक्ति पर कार्रवाई होनी थी,उसकी जगह पड़ोसी ग्राम सरईटिकरा के सरपंच एवं जनपद पंचायत सरपंच संघ के अध्यक्ष रामसाय मिंज को गिरफ्तार किए जाने का मामला तूल पकड़ गया है। कांग्रेस ने इसे महज प्रशासनिक भूल मानने से इनकार करते हुए इसे गंभीर लापरवाही और राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित कार्रवाई बताया है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि जनपद पंचायत के रिकॉर्ड इतने अव्यवस्थित हैं कि अधिकारियों को यह तक जानकारी नहीं कि किस गांव का सरपंच कौन है। इसी कथित चूक के चलते निर्दोष जनप्रतिनिधि को पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ा।

गबन चिताबहार में,कार्रवाई सरईटिकरा के सरपंच पर : जानकारी के अनुसार, वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत चिताबहार में सामुदायिक शौचालय निर्माण में 1,75,093 रुपये की कथित अनियमितता सामने आई थी। उस अवधि में चिताबहार के सरपंच शिवनाथ भगत तथा सचिव देवेन्द्र सिंह पदस्थ थे। बताया गया कि बाद में पदभार संभालने वाले सचिव ललित ने 23 जुलाई 2024 को कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अम्बिकापुर को लिखित पत्र भेजकर संबंधित मामले की जानकारी और तत्कालीन सरपंच का उल्लेख भी किया था। इसके बावजूद कार्रवाई चिताबहार के बजाय सरईटिकरा के सरपंच रामसाय मिंज के विरुद्ध आगे बढ़ती रही।

'मैं उस गांव का सरपंच ही नहीं था',फिर भी हुई गिरफ्तारी : कांग्रेस का दावा है कि रामसाय मिंज पहले ही लिखित स्पष्टीकरण देकर स्पष्ट कर चुके थे कि वे ग्राम सरईटिकरा के निवासी हैं तथा कथित गबन की अवधि में चिताबहार के सरपंच नहीं थे। इसके बावजूद शनिवार सुबह दरिमा पुलिस ने उन्हें खेत में काम करते समय हिरासत में ले लिया। आरोप है कि उन्हें कपड़े बदलने या दैनिक कार्य पूरे करने तक का अवसर नहीं दिया गया और सीधे एसडीएम न्यायालय में पेश कर दिया गया।

एसडीएम कोर्ट में जमानत से इनकार,मचा हड़कंप : मामले ने उस समय नया मोड़ ले लिया जब एसडीएम न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर रामसाय मिंज ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए जमानत लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि यदि प्रशासन उन्हें दोषी मानता है तो उन्हें जेल भेज दिया जाए। इस घटनाक्रम की जानकारी मिलते ही कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष राकेश गुप्ता,ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष विनय शर्मा,दरिमा ब्लॉक अध्यक्ष नारद गुप्ता, जनपद पंचायत अध्यक्ष विक्रम सोनपाकर,उपाध्यक्ष सतीश यादव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एसडीएम कार्यालय पहुंच गए। कुछ समय के लिए वहां तनावपूर्ण स्थिति भी बनी रही।

फिर जागा जनपद पंचायत,रिकॉर्ड की गलती स्वीकारने जैसा पत्र : घटनाक्रम के बाद जनपद पंचायत अम्बिकापुर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को भेजे गए पत्र में यह उल्लेख किया गया कि रिकॉर्ड में चिताबहार के सरपंच के स्थान पर रामसाय मिंज का नाम दर्ज होने के कारण उनके विरुद्ध कार्रवाई हो गई। कांग्रेस का कहना है कि यह पत्र स्वयं इस बात का प्रमाण है कि जनपद पंचायत अपने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का रिकॉर्ड तक सही ढंग से संधारित नहीं कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया कि यदि रिकॉर्ड में गलती थी तो उसकजिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की है या जनप्रतिनिधि की?

कांग्रेस का हमला: 'यह भूल नहीं, साजिश है' : कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने बताया कि उन्होंने पूरे मामले की जानकारी मिलने पर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) से फोन पर चर्चा कर तत्काल त्रुटि सुधारने और निर्दोष सरपंच के साथ हुए अन्याय को समाप्त करने की मांग की। पूर्व जिलाध्यक्ष राकेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि यह केवल प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि कांग्रेस समर्थित जनप्रतिनिधि को अपमानित करने की सुनियोजित साजिश है। उन्होंने कहा कि संबंधित सीईओ के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई, पद से हटाने और सार्वजनिक रूप से लिखित माफी मांगे जाने की आवश्यकता है।

अब उठ रहे कई बड़े सवाल...

- यदि गबन चिताबहार में हुआ तो कार्रवाई सरईटिकरा के सरपंच पर कैसे पहुंची?
- क्या जनपद पंचायत के रिकॉर्ड वर्षों से गलत दर्ज थे?
- यदि रिकॉर्ड गलत थे तो उनकी जिम्मेदारी किस अधिकारी की है?
- पहले दिए गए स्पष्टीकरण के बावजूद गिरफ्तारी क्यों हुई?
- क्या बिना तथ्यात्मक सत्यापन के पुलिस कार्रवाई कर दी गई?

इन सवालों के जवाब अब प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया हैं।

मौत के बाद भी नहीं मिला अपनों का साथ,महापौर ने कराया सम्मानजनक अंतिम संस्कार

75 वर्षीय महिला की मृत्यु पर परिजन और समाज नहीं पहुंचे,निगम की मदद से पूरी हुई अंतिम विदाई

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,31 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

वार्ड क्रमांक 4 शंकरनगर की 75 वर्षीय सावित्री बाई की मौत के बाद जब उनके अंतिम संस्कार के लिए न परिवार का कोई सदस्य आगे आया और न ही समाज के लोग, तब नगर निगम की महापौर मंजूषा भगत ने मानवीय पहल करते हुए उनका सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार कराया। घटना ने सामाजिक संवेदनाओं और रिश्तों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जाता है कि पति की मृत्यु के बाद सावित्री बाई ने वर्षों पहले दूसरे समाज के व्यक्ति से प्रेम विवाह कर लिया था। इसके बाद परिवार और समाज ने उनसे संबंध तोड़ लिए थे।

जीवनभर चला यह बहिष्कार उनकी मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं हुआ। महिला की कोई संतान भी नहीं थी। महापौर को जब जानकारी मिली कि महिला का अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं है, तो वे स्वयं मौके पर पहुंचीं। नगर निगम की व्यवस्था से जेसीबी के जरिए गड्ढा खुदवाया गया और सामाजिक परंपराओं के अनुसार

उनका सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार कराया गया। महापौर भी पूरे समय मौके पर मौजूद रहीं। बताया गया कि महिला के साथ रह रहे व्यक्ति ने अंतिम संस्कार करने की इच्छा जताई थी, लेकिन उसके परिजनों ने इसकी अनुमति नहीं दी।

महापौर बोलीं— इंसानियत सबसे बड़ा धर्म : महापौर मंजूषा भगत ने कहा कि किसी व्यक्ति के निधन के बाद भी यदि समाज और परिजन साथ न दें तो यह चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि अंतिम संस्कार हर व्यक्ति का सम्मानजनक अधिकार है और ऐसी परिस्थिति में मानवता निभाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।

CMYK

पुलिस महकमे में अनुशासन सर्वोपरि माना जाता है, ऐसे में स्थानांतरण आदेश के बाद भी कोरिया में मौजूदगी चर्चा का विषय बनी

-संवाददाता-
बैकुंठपुर,31 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा हाल ही में राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के तबादलों की सूची जारी की गई,जिसमें कोरिया जिले की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एडिशनल एसपी) सुरेशा चौबे का स्थानांतरण बिलासपुर जिले के लिए किया गया है,सामान्यतः पुलिस विभाग में स्थानांतरण आदेश जारी होने के बाद अधिकारी शीघ्र ही अपने नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण कर लेते हैं,क्योंकि पुलिस सेवा को अनुशासन और समयबद्ध कार्यप्रणाली के लिए जाना जाता है,लेकिन इस बार स्थिति कुछ अलग दिखाई दे रही है,सूत्रों के अनुसार स्थानांतरण आदेश जारी होने के बाद भी एडिशनल एसपी सुरेशा चौबे अब तक बिलासपुर में कार्यभार ग्रहण करने नहीं पहुंची हैं और अभी भी कोरिया जिले में मौजूद हैं,इसे लेकर प्रशासनिक और पुलिस महकमे में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

क्या तबादले से असंतुष्ट हैं?

कोरिया जिले में सुरेशा चौबे के बने रहने को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या वह अपने स्थानांतरण से संतुष्ट नहीं हैं? हालांकि इसका कोई आधिकारिक उत्तर फिलहाल उपलब्ध नहीं है,सूत्रों का दावा है कि वह अपने स्थानांतरण आदेश में संशोधन कराने के लिए प्रयासरत हैं,हालांकि इस संबंध में न तो स्वयं सुरेशा चौबे ने कोई बयान दिया है और न ही पुलिस मुख्यालय या गृह विभाग की ओर से कोई पुष्टि की गई है,इसलिए इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है।

कार्यकाल के दौरान कई संवेदनशील मामलों से जुड़ा रहा नाम

सुरेशा चौबे का कोरिया जिले में कार्यकाल भले ही बहुत लंबा नहीं रहा,लेकिन इस दौरान कई चर्चित और संवेदनशील घटनाएं सामने आईं,सबसे अधिक चर्चा सोनहत थाना क्षेत्र के नौगई तिहरा हत्याकांड की रही,इस घटना के दौरान वह प्रभारी पुलिस अधीक्षक का दायित्व भी संभाल रही थीं,घटना के बाद पुलिस की कार्रवाई, शुरुआती जांच और अधिकारियों के बयानों को लेकर लगातार सवाल उठे थे,पीड़ित परिवार ने सार्वजनिक रूप से पुलिस की कार्यप्रणाली पर असंतोष जताया था और कुछ अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए थे,हालांकि पुलिस विभाग ने समय-समय पर अपनी कार्रवाई और जांच को नियमसम्मत बताया था,इसके अलावा बैकुंठपुर क्षेत्र की कुछ अन्य घटनाओं को लेकर भी पुलिस की कार्यशैली चर्चा में रही।

क्या इन घटनाओं का तबादले से संबंध है?

राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में यह भी चर्चा है कि हालिया घटनाओं और कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों के कारण उनका स्थानांतरण किया गया,हालांकि यह केवल चर्चाओं और कयासों तक सीमित है, राज्य शासन द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश में किसी भी अधिकारी के तबादले का कारण उल्लेखित नहीं किया गया है, इसलिए यह कहना कि स्थानांतरण किसी विशेष घटना के कारण हुआ,फिलहाल तथ्यों के आधार पर स्थापित नहीं किया जा सकता।

पुलिस विभाग में ऐसे मामले कम देखने को मिलते हैं...

पुलिस विभाग में स्थानांतरण आदेश के बाद तत्काल कार्यभार ग्रहण करने की परंपरा रही है, अधिकांश मामलों में अधिकारी बिना विलंब नए पदस्थापना स्थल पर पहुंचकर जिम्मेदारी संभाल लेते हैं,यही कारण है कि एडिशनल एसपी के मामले में हो रही देरी प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बन गई है,यदि किसी अधिकारी को स्थानांतरण आदेश पर आपत्ति होती है या संशोधन की मांग करनी होती है, तो सामान्यतः शासन स्तर पर प्रक्रिया अपनाई जाती है,जब तक संशोधित आदेश जारी नहीं होता, तब तक मूल आदेश प्रभावी माना जाता है।

आधिकारिक चुप्पी से बढ़ रही अटकलें- इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक न तो पुलिस मुख्यालय और न ही एडिशनल एसपी सुरेशा चौबे की ओर से स्थानांतरण में देरी के कारणों पर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने आया है, यदि वास्तव में पदस्थापना आदेश में संशोधन के लिए आवेदन किया गया है,तो भी इसकी कोई अधिकृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।

कई सवालों के जवाब अभी बाकी, इस पूरे घटनाक्रम के बीच कई सवाल चर्चा में है-

- स्थानांतरण आदेश जारी होने के बाद भी नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण क्यों नहीं किया गया?
- क्या शासन से आदेश संशोधन का अनुरोध किया गया है?
- यदि किया गया है तो क्या उस पर कोई निर्णय लंबित है?
- क्या कोरिया जिले में अभी किसी विशेष प्रशासनिक दायित्व के कारण उन्हें रोका गया है?
- या फिर यह केवल विभागीय प्रक्रिया का हिस्सा है? इन सभी सवालों के स्पष्ट उत्तर फिलहाल उपलब्ध नहीं हैं।

अब शासन और पुलिस मुख्यालय की प्रतिक्रिया पर नजर–फिलहाल पूरा मामला अटकलों और सूत्रों के दावों के बीच है, अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या एडिशनल एसपी सुरेशा चौबे शीघ्र बिलासपुर में कार्यभार ग्रहण करेंगी या फिर शासन की ओर से उनके स्थानांतरण आदेश में कोई संशोधन जारी किया जाएगा, यदि आने वाले दिनों में कोई आधिकारिक आदेश या स्पष्टीकरण जारी होता है,तो इससे स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी।

ऑपरेशन क्लीन का नया दावा...24 घंटे में विक्रेता और सप्लायर गिरफ्तार लेकिन क्या अब भी बची हुई है नशे के नेटवर्क की सबसे बड़ी कड़ी?

'सुपरमैन' रंजीत गुप्ता की लगातार कार्रवाई... हर मामले में सप्लायर तक पहुंच रही टीम फिर भी हर कार्रवाई के बाद सामने आ रहा नया नाम...बड़े नेटवर्क पर सवाल बरकरार

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,31 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

संभागीय आबकारी उड़नदस्ता द्वारा चलाए जा रहे 'ऑपरेशन क्लीन' के तहत नशीले इंजेक्शनों के खिलाफ कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। शुक्रवार को टीम ने 24 घंटे के भीतर पहले अंबिकापुर से कथित विक्रेता अविनाश पैकरा और फिर बलरामपुर जिले के अनपारा क्षेत्र से उसके बताए कथित सप्लायर अमर विश्वकर्मा उर्फ बिट्टू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विभाग इसे ऑपरेशन क्लीन की बड़ी सफलता बता रहा है,लेकिन लगातार हो रही ऐसी कार्रवाइयों के बावजूद यह सवाल और गहरा होता जा रहा है कि आखिर इस पूरे अवैध कारोबार की सबसे ऊपरी कड़ी कब बेनकाब होगी। आबकारी विभाग के अनुसार 30 जुलाई को मुखबिर की सूचना पर शांतिपारा स्थित किराए के मकान में दबिश देकर अविनाश पैकरा को गिरफ्तार किया गया। उसके बैग से 15-15 नग रेक्सोजेसिक और एविल इंजेक्शन बरामद हुए। पूछताछ में उसने बताया कि वह इंजेक्शन बलरामपुर जिले के अनपारा निवासी अमर विश्वकर्मा उर्फ बिट्टू से खरीदकर लाता है। इसके बाद 31 जुलाई को उड़नदस्ता टीम ने बलरामपुर पहुंचकर विमलापुर के जंगल से बिट्टू को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 50-50 नग रेक्सोजेसिक और एविल इंजेक्शन बरामद किए गए। दोनों आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता का दावा है कि ऑपरेशन क्लीन के कारण अंबिकापुर के लगभग 90 प्रतिशत नशीले इंजेक्शन विक्रेता जेल पहुंच चुके हैं। उनका कहना है कि अब कुछ लोग बलरामपुर और सूरजपुर से माल लाकर बेचने का प्रयास कर रहे हैं और विभाग की नजर उन पर भी है।

लगातार एक ही पैटर्न,हर बार अगली कड़ी तक पहुंचने का दावा : पिछले कुछ माह में आबकारी उड़नदस्ता की कार्रवाई का लगभग एक जैसा पैटर्न सामने आया है। पहले वाहिद अंसारी की गिरफ्तारी के बाद मोशीम अंसारी तक टीम पहुंची। इसके बाद श्याम लॉज से पकड़े गए साहिल तिर्की के बयान पर नितीश गुप्ता गिरफ्तार हुआ। सीतापुर में सजाद अली से पूछताछ के बाद महबूब खान तक कार्रवाई पहुंची। ब्रह्मपारा में आशा पांडेय की गिरफ्तारी के बाद उसके बताए कथित सप्लायर राजेश मंदिलवार उर्फ बुटन को जेल भेजा गया। अब अविनाश पैकरा से पूछताछ के बाद अमर विश्वकर्मा उर्फ बिट्टू की गिरफ्तारी हुई है। इससे स्पष्ट है कि टीम केवल बरामदगी तक सीमित नहीं रहकर सप्लाई चेन की अगली कड़ी तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।

महुआ शराब से लेकर नशीले इंजेक्शन तक लगातार दबिश

ऑपरेशन क्लीन के दौरान केवल नशीले इंजेक्शनों पर ही नहीं,बल्कि अवैध महुआ शराब के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। हाल ही में गंगापुर के नालापारा में विजय गिरी के घर दबिश देकर 15 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब, 200 किलोग्राम महुआ लाहन और चलती भट्ठी बरामद की गई थी। इससे पहले हजारों नशीले कैप्सूल और अन्य मादक पदार्थ भी जब्त किए जा चुके हैं। लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से विभाग की सक्रियता तो दिखाई देती है,लेकिन यह भी साफ है कि अवैध कारोबार अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।

90 प्रतिशत विक्रेता जेल में...फिर भी बाजार में कैसे पहुंच रहे इंजेक्शन?

सुपरमैन आबकारी अधिकारी का दावा है कि अंबिकापुर के 90 प्रतिशत नशीले इंजेक्शन विक्रेता जेल भेजे जा चुके हैं। यदि यह दावा सही है तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसके बावजूद नए विक्रेता और नए सप्लायर लगातार कैसे सामने आ रहे हैं? क्या नेटवर्क ने केवल अपना ठिकाना बदल लिया है या इसके पीछे कोई ऐसी बड़ी आपूर्ति श्रृंखला काम कर रही है, जो अभी तक जांच की पहुंच से बाहर है?

अब असली परीक्षा नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने की...

लगातार सफल कार्रवाई निश्चित रूप से विभाग की सक्रियता को दर्शाती है, लेकिन हर गिरफ्तारी के बाद एक नया सप्लायर सामने आना यह भी संकेत देता है कि नशे का कारोबार अभी कई स्तरों पर सक्रिय है। आम लोगों की अपेक्षा अब केवल फुटकर विक्रेताओं की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि उस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश है जहां से जिले और संभाग में नशीले इंजेक्शन एवं अन्य मादक पदार्थों की आपूर्ति हो रही है। यदि जांच उस शीर्ष स्तर तक पहुंचती है, तभी ऑपरेशन क्लीन को वास्तविक और स्थायी सफलता माना जाएगा।

शराब पीकर बाइक चलाना पड़ा महंगा,दो चालकों पर 20 हजार रुपये का जुर्माना

ड्रंक एंड ड्राइव के दो मामलों में न्यायालय ने प्रत्येक चालक पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया,यातायात पुलिस की कार्रवाई जारी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,31 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

सरगुजा पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत ड्रंक एंड ड्राइव के दो मामलों में मोटरसाइकिल चालकों पर सख्त कार्रवाई की गई। दोनों मामलों में वाहन चालकों के शराब के नशे में वाहन चलाते पाए जाने पर धारा 185 मोटर वाहन अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां दोनों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। कुल मिलाकर 20 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल के निर्देशन में यातायात शाखा की टीम ने चेकिंग के दौरान बाइक क्रमांक CG-29-AG-3955 के चालक राजू राजवाड़े (24), निवासी बतरा, थाना जयनगर, जिला सूरजपुर को रोका। ब्रेथ एनालाइजर जांच में चालक के शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई। इसी प्रकार दूसरी कार्रवाई में

बाइक क्रमांक CG-15-ED-3861 के चालक राकेश तिर्की (29),निवासी पटपरिया, थाना गांधीनगर को भी शराब के नशे में वाहन चलाते पकड़ा गया। जांच में नशे की पुष्टि होने पर दोनों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि शराब का सेवन कर वाहन न चलाएं और यातायात नियमों का पालन करें। अभियान के तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। सम्पूर्ण कार्रवाई में यातायात शाखा प्रभारी उप निरीक्षक विजय कैवर्त एवं उनकी टीम की सक्रिय भूमिका रही।

कीटनाशक सेवन कर प्यून ने दी जान

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,31 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

प्रतापपुर न्यालया के प्यून ने अज्ञात कारण से कीटनाशक सेवन कर लिया था। परिजन उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया था। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ओम प्रकाश उम्र 53 वर्ष ग्राम भिटवा थाना सीतापुर का रहने वाला था। वह प्रतापपुर न्यायालय में प्यून के पद पर कार्यरत था। इसकी शादी नहीं हुई थी। वह 27 जुलाई को अज्ञात कारण से प्रतापपुर बाजार डांड में कीटनाशक सेवन कर लिया था। उसे इलाज के लिए प्रतापपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां डॉक्टर ने उसकी स्थिति को गंभीर देखते हुए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया था। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

पर्यावरण बचाने से पहले मन का प्रदूषण दूर करें : टी.एस. सिंहदेव

ब्रह्माकुमारीज़ के पर्यावरण संरक्षण एवं आपदा प्रबंधन अभियान का अंबिकापुर में आयोजन

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,31 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय की ओर से 26 जुलाई से 6 अगस्त तक संचालित पर्यावरण संरक्षण एवं आपदा प्रबंधन अभियान के तहत अंबिकापुर में प्रेरणादायी कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए सबसे पहले मन के पर्यावरण को शुद्ध करना होगा। यदि हम अपने विचारों को सकारात्मक नहीं बनाएंगे तो बाहरी प्रदूषण और प्राकृतिक असंतुलन को रोक पाना कठिन होगा। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। अतिथियों का स्वागत पौधे एवं बैज भेंट कर किया गया। ब्रह्माकुमारीज़ अंबिकापुर सेवा केंद्र की संचालिका बीके विद्या दीदी ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए अभियान के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि ब्रह्माकुमारीज़ की सेवाओं से वे लंबे समय से जुड़े हैं और यहां आकर हमेशा आत्मिक शांति का अनुभव होता है। उन्होंने कहा कि विकास की अंधी दौड़ में मानव ने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया है। अब समय आ गया है कि हम अपने विचारों और जीवनशैली में बदलाव लाकर प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी निभाएं।

नगर निगम सभापति हरमिंदर सिंह टिन्नी ने कहा कि अभियान से मिली प्रेरणाओं को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत को पुनः समृद्ध और विश्व में सम्मानित बनाने के लिए प्रकृति

और संस्कार दोनों का संरक्षण आवश्यक है। दिल्ली से आए बीके पीयूष भाई ने कहा कि हर व्यक्ति को हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत स्वयं से होती है। जल्दी सोना-जल्दी उठना, सकारात्मक चिंतन करना और सिंगल यूज प्लास्टिक से दूरी बनाना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। माउंट आबू से आए बीके ओंकार भाई ने अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन-जागरण के साथ लोगों को आपदा प्रबंधन के प्रति भी जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि बाहरी प्रदूषण को रोकने से पहले मन के भीतर के प्रदूषण को समाप्त करना होगा। पानीपत से आई बीके ज्योति दीदी ने राजयोग का महत्व बताते हुए कहा कि राजयोग आत्मा और परमात्मा का मिलन है। उन्होंने सभी को हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहने, दूसरों की विशेषताओं को देखने और सकारात्मक सोच अपनाने का संदेश दिया। उन्होंने राजयोग मेडिटेशन का भी अभ्यास कराया। कार्यक्रम में ब्रह्माकुमारी बहनों ने अतिथियों को ईश्वरीय साहित्य, प्रसाद एवं स्मृति-चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। मणिकर्णिका और अदिति ने स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में समाजसेवी शिल्पा पांडे, मंगल पांडे,वंदना दत्ता,आर्ट ऑफ लिविंग के संचालक अजय तिवारी, सुधीर पांडे सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अभियान के तहत साईं बाबा कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, साइंस कॉलेज तथा विश्रामपुर एसईसीएल में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम का संचालन बीके तारीका दीदी ने किया।

डीआईजी-एसएसपी राजेश अग्रवाल ने किया रक्षित केंद्र का वार्षिक निरीक्षण उत्कृष्ट जवान हुए सम्मानित

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,31 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल ने शुक्रवार को रक्षित केंद्र अंबिकापुर का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण की शुरुआत परेड की सलामी लेकर की गई। इसके बाद मार्च पास्ट,स्कॉट ड्रिल और परेड का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों एवं जवानों के टर्नआउट की जांच की गई। परेड में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जवानों को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने वाहन शाखा का विस्तृत अवलोकन करते हुए शासकीय वाहनों की स्थिति,रखरखाव,लॉग बुक एवं दस्तावेजों की समीक्षा की। उन्होंने बीपी वाहन, जैमर वाहन सहित सभी वाहनों को बेहतर स्थिति में बनाए रखने और रिकॉर्ड अद्यतन रखने के निर्देश दिए। इसके बाद आर्म्स शाखा, स्टोर शाखा एवं पुलिस यूनिट बैंक का निरीक्षण किया गया। हथियारों की नियमित साफ-सफाई एवं सुरक्षित रखरखाव, स्टोर सामग्री के सुव्यवस्थित वितरण तथा आवश्यक उपकरणों के समय-समय पर रखरखाव के निर्देश दिए गए। पुलिस यूनिट बैंक के माध्यम से जवानों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं को और प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया गया। निरीक्षण के दौरान डीआईजी-एसएसपी ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और उनके शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों को आमजन के प्रति संवेदनशील व्यवहार रखने तथा जनता का विश्वास जीतने के लिए निष्पक्ष एवं जिम्मेदारी से कार्य करने की नसीहत दी। इस अवसर पर पुलिस मुख्यालय से प्राप्त नए शासकीय वाहन का पूजन भी किया गया और उसके बेहतर रखरखाव के निर्देश दिए गए।

एक साल... 50 से ज्यादा खबरें... फिर भी न पुल बना, न बचा विकल्प!

पहले पुल टूटा, फिर रपटा बहा!

एक साल बाद भी अधूरा समाधान, ग्रामीण बेहाल

जनता का सवाल
आखिर जाएं तो जाएं कैसे?

30 जून 2025 को ध्वस्त हुआ पुल, 18 जुलाई 2026 को बहा 15 लाख का रपटा

- 50+ खबरें, लगातार फॉलोअप
- 15 लाख का रपटा भी नहीं टिक पाया
- एप्रोच रोड, WMM कार्य के बाद भी समाधान नहीं
- हजारों ग्रामीण आज भी लंबा चक्कर लगाने को मजबूर
- स्थायी पुल कब बनेगा? जवाबदेही कौन तय करेगा?

एक साल में दो बार टूटा संपर्क...पहले पुल ध्वस्त,अब बह गया रपटा! गोबरी

नदी पर विकास की परीक्षा में कौन फेल हुआ-पुल,रपटा या पूरी व्यवस्था?

ना स्थायी पुल बचा...ना वैकल्पिक रपटा,आखिर ग्रामीण जाएं तो जाएं कैसे?

- एक साल...50 से ज्यादा खबरें...पहले पुल टूटा,फिर रपटा बहा,फिर भी समाधान अधूरा!
- ना स्थायी पुल...ना वैकल्पिक रपटा,आखिर हजारों ग्रामीणों की जिम्मेदारी किसकी?
- पहले पुल गया...फिर रपटा गया...अब जनता जाए तो जाए कैसे?
- 'दैनिक घटती-घटना' की 50 से ज्यादा खबरें...फिर भी पुल अधूरा,रपटा बहा और संपर्क टूटा
- एक साल में दो बार टूटा संपर्क...पहले पुल ध्वस्त,फिर बहा 15 लाख का रपटा
- 50 से ज्यादा खबरें,दर्जनों फॉलोअप...फिर भी न पुल बना,न बचा विकल्प!

ओंकार पांडेय

सूरजपुर,31 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

किसी भी विकास कार्य की सफलता का पैमाना उसका उद्घाटन नहीं,बल्कि उसकी उपयोगिता और टिकाऊपन होता है,लेकिन डुमरिया-केवरा-भैयाथान पहुंच मार्ग पर गोबरी नदी की कहानी कुछ अलग ही बयां कर रही है,यहां 30 जून 2025 को करोड़ों की लागत से बना मुख्य पुल धराशायी हो गया,उस दिन से लेकर आज तक पूरा एक वर्ष बीत चुका है,जुलाई 2026 का महीना भी समाप्त हो गया, लेकिन न तो नया स्थायी पुल बन पाया और न ही वैकल्पिक व्यवस्था टिक सकी,अब स्थिति यह है कि न स्थायी पुल बचा है और न ही वैकल्पिक रपटा, ऐसे में हजारों ग्रामीण एक बार फिर उसी सवाल के साथ खड़े हैं–'आखिर अब जाएं तो जाएं कैसे?'बता दे की पत्रकारिता का उद्देश्य केवल खबर प्रकाशित करना नहीं,बल्कि जनहित के मुद्दों को तब तक उठाना है,जब तक समाधान नहीं हो जाता,गोबरी नदी पर टूटे पुल का मामला इसका सबसे बड़ा उदाहरण बन गया है,30 जून 2025 को गोबरी नदी पर बना पुल टूटा,उसी दिन से दैनिक घटती-घटना ने इस मामले को केवल एक दुर्घटना की खबर मानकर नहीं छोड़ा, बल्कि इसे जनहित का अभियान बनाया, पिछले एक वर्ष में इस एक मुद्दे पर 50 से अधिक प्रमुख समाचार,खोजी रिपोर्ट, विश्लेषण, फॉलोअप,ग्राउंड रिपोर्ट, संपादकीय और व्यंग्यात्मक रिपोर्ट प्रकाशित की गई,हर खबर का उद्देश्य केवल एक था– हजारों ग्रामीणों को सुरक्षित आवागमन मिले और स्थायी समाधान हो,लेकिन एक वर्ष बाद स्थिति यह है कि न स्थायी पुल तैयार है और न ही वैकल्पिक व्यवस्था सुरक्षित बची है।

दैनिक घटती-घटना ने जो लिखा...वह सच साबित होता गया- जब रपटा बन रहा था,तब अखबार ने सवाल उठाया–'क्या यह पहली बरसात झेल पाएगा?'जब सड़क अधूरी थी,तब लिखा– 'रपटा बना...लेकिन जनता अब भी कीचड़ में।'जब डब्ल्यूएमएम शुरू हुआ,तब लिखा–'अब पहली बरसात बताएगी निर्माण की असली कहानी।'और जब बारिश आई तो रपटा बह गया,अब सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या यह केवल संयोग था या फिर अखबार द्वारा पहले उठाए गए तकनीकी और गुणवत्ता संबंधी प्रश्नों पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया?

'दैनिक घटती-घटना' का अभियान जारी रहेगा-पुल टूटने से लेकर रपटा बनने, सड़क बनने,रपटा बहने और फिर संपर्क टूटने तक दैनिक घटती-घटना ने इस जनहित के मुद्दे को लगातार प्रमुखता से उठाया है,एक वर्ष...50 से अधिक खबरें...दर्जनों ग्राउंड रिपोर्ट...फिर भी समाधान अधूरा,जब तक गोबरी नदी पर स्थायी पुल बनकर हजारों ग्रामीणों का सुरक्षित आवागमन बहाल नहीं हो जाता,तब तक यह अभियान जारी रहेगा।

एक वर्ष पहले टूटा पुल,आज भी अधूरी है कहानी-30 जून 2025 को गोबरी नदी पर बना पुल अचानक क्षतिग्रस्त होकर उपयोग के लायक नहीं रहा, प्रशासन ने तत्काल पुल पर आवागमन बंद कर दिया, यह पुल केवल एक संरचना नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-43 से भैयाथान बनारस राज्यकीय राज्य मार्ग के बीच दर्जनों गांवों को जोड़ने वाली जीवनरेखा था,पुल टूटने के साथ ही डुमरिया,केवरा,भैयाथान और आसपास के अनेक गांवों का सीधा संपर्क मुख्य मार्ग से टूट गया,ग्रामीणों को कई किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ी, मरीजों को अस्पताल पहुंचने में अधिक समय लगने लगा,विद्यार्थियों को स्कूल-कॉलेज जाने में परेशानी हुई और किसानों के परिवहन खर्च में बढ़ोतरी हो गई,उस समय कहा गया था कि जल्द नया पुल बनेगा, लेकिन एक वर्ष बाद भी यह स्पष्ट नहीं है कि स्थायी पुल का निर्माण कब शुरू होगा और कब पूरा होगा।

एक साल बाद मिला केवल रपटा...वह भी नहीं टिक पाया-लगातार जनदबाव और दैनिक घटती-घटना द्वारा किए गए फॉलो-अप के बाद विभाग ने लगभग 15 लाख रुपये की लागत से वैकल्पिक रपटा तैयार कराया,लोगों को लगा कि अब कम से कम बरसात के दौरान संपर्क बना रहेगा,लेकिन यह राहत अधिक दिनों तक नहीं टिक सकी,लगातार तीन दिनों की बारिश के बाद रपटा क्षतिग्रस्त हो गया और आवागमन फिर बाधित हो गया,अब ग्रामीणों के सामने वही पुरानी परेशानी खड़ी हो गई है।

एक साल की पत्रकारिता...एक साल का इंतजार...

इस अभियान की शुरुआत 30 जून 2025 को पुल टूटने की पहली खबर से हुई,इसके बाद लगातार प्रकाशित खबरों में हर पहलू उठाया गया पुल क्यों टूटा? निर्माण गुणवत्ता कैसी थी? नया पुल कब बनेगा? करोड़ों के पुल की गति और 15 लाख के रपटा की सुस्ती, ग्रामीणों की परेशानी,प्रशासनिक निरीक्षण,तकनीकी सवाल,रपटा निर्माण,अधूरी एप्रोच रोड,जनता द्वारा चंदा अभियान,डब्ल्यूएमएम कार्य,पहली बरसात में रपटा की परीक्षा,रपटा का बह जाना,फिर से संपर्क टूटना,हर चरण पर दैनिक घटती-घटना ने केवल समाचार नहीं छापे,बल्कि दस्तावेज,स्थल निरीक्षण,तस्वीरें और जमीनी तथ्यों के साथ पूरा घटनाक्रम जनता के सामने रखा।

अभियान का असर भी दिखा...

लगातार प्रकाशित खबरों का असर कई बार दिखाई भी दिया, प्रशासन ने निरीक्षण किया, वैकल्पिक रपटा बनाया गया,एप्रोच रोड की समस्या उजागर होने के बाद डब्ल्यूएमएम कार्य शुरू हुआ,निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठने के बाद तकनीकी चर्चा शुरू हुई,लेकिन इन सबके बावजूद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न–स्थायी पुल–आज भी अधूरा है।

दैनिक घटती-घटना ने पहले ही जताई थी आशंका...

रपटा बनने के बाद 7 जुलाई 2026 को दैनिक घटती-घटना ने प्रमुखता से समाचार प्रकाशित कर सवाल उठाया था कि गोबरी नदी के तेज बहाव के सामने इस वैकल्पिक व्यवस्था की वास्तविक परीक्षा पहली बरसात में होगी,समाचार में यह भी उल्लेख किया गया था कि नदी का जलग्रहण क्षेत्र पहाड़ी है और बरसात में यहां पानी का बहाव अत्यंत तेज हो जाता है। यदि निर्माण पर्याप्त मजबूत नहीं हुआ तो रपटा पर खतरा पैदा हो सकता है,अब रपटा के क्षतिग्रस्त होने के बाद ग्रामीणों के बीच यही चर्चा है कि अखबार द्वारा उठाई गई आशंका सही साबित होती दिखाई दे रही है।

अब न स्थायी व्यवस्था,न विकल्प

आज सबसे बड़ी विडंबना यही है कि एक वर्ष बाद भी स्थिति वहीं आकर खड़ी हो गई है, पहले पुल टूटा, फिर वैकल्पिक रपटा बना,अब रपटा भी नहीं बचा,ऐसे में लोगों के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर प्रशासन की तत्काल कार्ययोजना क्या है? क्या नया रपटा बनेगा? क्या अस्थायी पुल बनाया जाएगा? क्या बरसात खत्म होने तक लोगों को लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा? इन सवालों का उत्तर फिलहाल स्पष्ट नहीं है।

10 किलोमीटर का सफर अब कई किलोमीटर लंबा

जो दूरी पहले लगभग 10 किलोमीटर में पूरी हो जाती थी, अब लोगों को कई किलोमीटर अतिरिक्त घूमकर तय करनी पड़ रही है,इसका सीधा असर आम लोगों की जेब और समय दोनों पर पड़ रहा है,ईंधन की खपत बढ़ गई, यात्रा का समय बढ़ गया,किसानों का परिवहन खर्च बढ़ गया,मरीजों के लिए अस्पताल पहुंचना कठिन हो गया,विद्यार्थियों की नियमित पढ़ाई प्रभावित हो रही है,एक पुल टूटने का असर केवल सड़क तक सीमित नहीं रहता,बल्कि पूरे ग्रामीण जीवन पर पड़ता है।

डुमरिया-केवरा-भैयाथान मार्ग की जीवनरेखा थ्प

लगभग 18 किलोमीटर लंबे डुमरिया-केवरा-भैयाथान मार्ग पर राष्ट्रीय राजमार्ग-43 से लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्थित यह पुल वर्षों से क्षेत्र की मुख्य कड़ी था,हजारों लोग प्रतिदिन इसी रास्ते से आवागमन करते थे,पुल टूटने के बाद लोगों ने सोचा था कि कुछ महीनों की परेशानी होगी, लेकिन अब एक वर्ष बीत चुका है और स्थायी समाधान अभी भी दूर दिखाई दे रहा है।

व्यंग्यः विकास की नई परिभाषा

सरकारी फाइलों में शायद यह लिखा होगा कि वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई,जमीनी हकीकत कहती है पहले पुल टूटा...फिर कहा गया–रपटा बनेगा,रपटा बना...फिर कहा गया– सड़क बनेगी,सड़क बनी...फिर कहा गया–अब समस्या खत्म, लेकिन तीन दिन की बारिश ने सारी घोषणाओं का ऐसा 'निरीक्षण' किया कि पूरी व्यवस्था फिर वहीं पहुंच गई,जहां से यात्रा शुरू हुई थी,अब ग्रामीण मजाक में कह रहे हैं यहां विकास का काम पानी के भरोसे होता है,अगर पानी ने मंजूर कर लिया तो निर्माण चलेगा,नहीं तो फिर नई घोषणा होगी।

चुप्पी भी सवाल बन गई...

जब पुल टूटा था तब अधिकारी पहुंचे थे,जब रपटा बना तब निरीक्षण हुए थे,जब सड़क बनी तब तस्वीरें खिंची थीं,लेकिन अब जब रपटा भी क्षतिग्रस्त हो गया है,तब सबसे अधिक चर्चा किसी बयान की नहीं,बल्कि खामोशी की है,ग्रामीण पूछ रहे हैं क्या अब कोई जिम्मेदार अधिकारी बताएगा कि आगे क्या होगा? क्या कोई समय-सीमा घोषित होगी? क्या स्थायी पुल के निर्माण की तिथि सार्वजनिक की जाएगी?

अब जवाबदेही तय होनी चाहिए...

इस पूरे घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, यदि रपटा वास्तव में तेज बहाव के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है,तो यह तकनीकी समीक्षा का विषय है,क्या नदी के बहाव का पर्याप्त अध्ययन किया गया था? क्या डिजाइन परिस्थितियों के अनुरूप थी? क्या निर्माण के बाद नियमित निरीक्षण हुआ? क्या भविष्य के लिए बेहतर वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाएगी? इन सभी प्रश्नों पर विभाग को सार्वजनिक रूप से स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

'घटती-घटना' के बड़े सवाल

- एक वर्ष बाद भी स्थायी पुल निर्माण कब शुरू होगा?
- वैकल्पिक रपटा के क्षतिग्रस्त होने के बाद तत्काल आवागमन की क्या व्यवस्था है?
- हजारों ग्रामीणों को कब तक लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा?
- क्या निर्माण की तकनीकी जांच कराई जाएगी?
- क्या जिम्मेदारी तय होगी?
- क्या सरकार और संबंधित विभाग इस मार्ग को फिर से चालू करने की समय-सीमा घोषित करेंगे?

अंतिम सवाल...एक वर्ष पहले कहा गया था...

'कुछ समय की परेशानी है,आज एक वर्ष बाद सवाल बदल चुका है जब न स्थायी पुल बचा, न वैकल्पिक रपटा,तो आखिर हजारों ग्रामीणों की रोजमर्रा की जिंदगी किसके भरोसे चले? यही प्रश्न अब केवल ग्रामीणों का नहीं,बल्कि उस पूरे प्रशासनिक तंत्र के सामने है,जिसे विकास कार्यों को समय पर पूरा करने और आम लोगों का जीवन सुगम बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

अब सवाल सिर्फ पुल का नहीं,जवाबदेही का है...

एक वर्ष में 50 से अधिक खबरें प्रकाशित होने के बाद भी यदि स्थिति वहीं की वहीं है, तो सवाल केवल निर्माण एजेंसी पर नहीं, बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र पर उठता है,क्या जिम्मेदारी तय होगी? क्या निर्माण गुणवत्ता की स्वतंत्र जांच होगी? क्या दोषी अधिकारियों और एजेंसी पर कार्रवाई होगी? क्या स्थायी पुल की समय-सीमा सार्वजनिक की जाएगी?

महिला कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री पहलाद जोशी और सांसद कंगना रनौत का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया

कथित विवादित बयानों के विरोध में प्रदर्शन,सार्वजनिक माफी की उठाई मांग

-संवाददाता-

मनेंद्रगढ़,31 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लाम्बा के निर्देश एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश महिला कांग्रेस की कार्यवाहक अध्यक्ष संगीता सिन्हा के मार्गदर्शन में जिला महिला कांग्रेस,मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) द्वारा शुक्रवार को राजीव गांधी चौक (खेड़िया टॉकीज़ के पास) केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी और भाजपा सांसद कंगना रनौत के विरोध में प्रतीकात्मक पुतला दहन कर प्रदर्शन किया गया। महिला कांग्रेस की पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी के कथित विवादित बयान तथा सांसद कंगना रनौत द्वारा देश की युवा पीढ़ी की बेटियों के संबंध में की गई कथित टिप्पणी महिलाओं के सम्मान के प्रतिकूल है,प्रदर्शनकारियों ने दोनों नेताओं से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की।

महिलाओं के सम्मान से समझौता नहीं : प्रभा पटेल-पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल ने कहा कि महिलाओं का सम्मान प्रत्येक जनप्रतिनिधि की प्राथमिक जिम्मेदारी है,उन्होंने कहा कि महिलाओं के संबंध में किसी भी प्रकार की अपमानजनक या असंवेदनशील टिप्पणी स्वीकार्य नहीं हो सकती,उन्होंने कहा कि महिला कांग्रेस महिलाओं के सम्मान और अधिकारों से जुड़े हर मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी।

गलत संदेश देते हैं ऐसे बयान-पूर्व प्रदेश महामंत्री रुकमणी खोपरागढ़े ने कहा कि महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले कथित बयानों से समाज में गलत संदेश जाता है। उन्होंने संबंधित नेताओं से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की,जिला कांग्रेस महामंत्री पूनम सिंह ने कहा कि देश की बेटियों के आत्मसम्मान पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और महिला कांग्रेस लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराती रहेगी।

संयमित भाषा की दी नसीहत-पूर्व जिला अध्यक्ष (शहर) रूमा चटर्जी ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की भाषा मर्यादित और जिम्मेदार होनी चाहिए, वहीं पूर्व जिला अध्यक्ष (ग्रामीण) निर्मला चतुर्वेदी ने कहा कि यह विरोध महिलाओं के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए किया गया है।

बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता रहीं मौजूद-प्रदर्शन में पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष महिला कांग्रेस शोभना वर्मा, पार्षद किरण कुजूर,पूर्व पार्षद हमीदा खातून, बबीता यादव,शशि चंदेल,नीलमां शामल,ममता रजक,सीताकली,दीपा सिंह,सरोज,ज्योति,शकीला बाला सहित महिला कांग्रेस की अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहीं।

कोरिया वन मंडल में निर्माण कार्यों पर उठे गंभीर सवाल

जब जेसीबी और ट्रैक्टर से बने तालाब, तो मस्टर रोल में किन मजदूरों के नाम चढ़े?

कोरिया जन सहयोग समिति के कार्यकारी अध्यक्ष अधिवक्ता जय सोनपाकर का बड़ा हमला

सोनहत, बैकुंठपुर और देवगढ़ रेंज में मजदूरी भुगतान एवं निर्माण कार्यों की उच्चस्तरीय जांच की मांग

मशीन बनाम मजदूर का परीक्षण: मस्टर रोल, भुगतान विवरण और वास्तविक कार्यस्थलों का हो मिलान

बैंक भुगतान का सत्यापन: जिन खातों में मजदूरी की राशि भेजी गई, उनकी हो गहन जांच

तकनीकी एवं भौतिक जांच: मेजरमेंट बुक का परीक्षण कर स्वतंत्र विशेषज्ञों से हो भौतिक सत्यापन

रणनीति तय करने समिति की अहम बैठक, आंदोलन और कानूनी कार्रवाई पर लिए जा सकते हैं बड़े निर्णय

जेसीबी से बने तालाब,तो मस्टर रोल में किन मजदूरों के नाम चढ़े?

कार्यकारी अध्यक्ष अधिवक्ता जय सोनपाकर बोले...'यदि मशीनों से हुआ काम,तो मजदूरी किसे मिली? बैंक खातों से लेकर मस्टर रोल तक हो निष्पक्ष जांच'

-रवि सिंह-
बैकुंठपुर (कोरिया),31 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

कोरिया वन मंडल में तालाब निर्माण,रेंगान, वृक्षारोपण,एनिकेट एवं अन्य कैम्पा कार्यों को लेकर उठ रहे कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोपों के बीच अब एक नया और बेहद गंभीर सवाल सामने आया है, सवाल केवल निर्माण गुणवत्ता या पहली बारिश में क्षतिग्रस्त हुए तालाबों तक सीमित नहीं है, बल्कि अब सरकारी अभिलेखों में दर्ज मजदूरी भुगतान की पारदर्शिता पर भी प्रश्न उठने लगे हैं। कोरिया जन सहयोग समिति के कार्यकारी अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता जय सोनपाकर ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यदि अधिकांश निर्माण कार्य जेसीबी और ट्रैक्टर जैसी भारी मशीनों से कराए गए,तो सरकारी मस्टर रोल में दर्ज हजारों मजदूर आखिर कौन थे और उन्हें किस आधार पर भुगतान किया गया? उन्होंने पूरे मामले की स्वतंत्र, तकनीकी एवं वित्तीय जांच की मांग करते हुए कहा कि अब केवल सोनहत ही नहीं, बल्कि बैकुंठपुर और देवगढ़ वन परिक्षेत्रों के निर्माण कार्यों की भी जांच आवश्यक हो गई है।

तालाब से शुरू हुआ विवाद अब मजदूरी भुगतान तक पहुंचा-सोनहत वन परिक्षेत्र में तालाब निर्माण को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब पहली ही बारिश में कुछ निर्माण कार्य क्षतिग्रस्त होने की शिकायतें सामने आईं, इसके बाद निर्माण गुणवत्ता,मशीनों के उपयोग, सूचना पट्ट नहीं लगाए जाने और कथित तकनीकी अनियमितताओं को लेकर लगातार सवाल उठने लगे,दैनिक घटती-घटना द्वारा इन मुद्दों को प्रमुखता से प्रकाशित किए जाने के बाद सामाजिक संगठन, जनप्रतिनिधि और राजनीतिक दल भी सक्रिय हुए, मुख्यमंत्री को शिकायतें भेजी गईं,डीएफओ और एसडीओ फॉरेस्ट को ज्ञापन सौंपे गए,पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने पीसीसीएफ से चर्चा की, नागरिक एकता मंच ने आंदोलन की चेतावनी दी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भी जांच की मांग उठाई, अब इस पूरे विवाद में सबसे गंभीर प्रश्न मजदूरी भुगतान का जुड़ गया है।

केवल सोनहत नहीं,तीनों वन परिक्षेत्रों की हो जांच-जय सोनपाकर ने कहा कि मामला अब केवल सोनहत वन परिक्षेत्र तक सीमित नहीं रह गया है,उन्होंने मांग की कि सोनहत, बैकुंठपुर, देवगढ़ तीनों वन परिक्षेत्रों में पिछले एक से दो वर्षों के दौरान कराए गए तालाब,रेंगान,एनिकेट,वृक्षारोपण और अन्य विकास कार्यों की स्वतंत्र जांच कराई जाए, उनका कहना है कि यदि शिकायतें कई स्थानों से सामने आ रही हैं,तो जांच भी व्यापक दायरे में होनी चाहिए।

रणनीति तय करने होगी विशेष बैठक-वन विभाग में कथित भ्रष्टाचार, मशीनों के उपयोग,मजदूरी भुगतान और निर्माण गुणवत्ता से जुड़े मुद्दों पर आगे की रणनीति तय करने के लिए कोरिया जन सहयोग समिति ने विशेष बैठक बुलाने का निर्णय लिया है,बैठक में अधिवक्ता,सामाजिक कार्यकर्ता,जन प्रतिनिधि और समिति के पदाधिकारी उपलब्ध दस्तावेजों की समीक्षा करेंगे,सूत्रों के अनुसार बैठक में आंदोलन की रूपरेखा, शासन को नई शिकायतें,आरटीआई के माध्यम से अतिरिक्त दस्तावेज जुटाने,तथा न्यायालय में याचिका दायर करने जैसे विषयों पर भी चर्चा हो सकती है।

बढ़ता जा रहा है दबाव-वन विभाग पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है,अब तक ग्रामीणों ने शिकायतें कीं,दैनिक घटती-घटना ने लगातार खोजी समाचार प्रकाशित किए,कोरिया जन सहयोग समिति ने ज्ञापन सौंपा,मुख्यमंत्री को शिकायत भेजी गई, पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने पीसीसीएफ से चर्चा की,गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने आंदोलन की चेतावनी दी, नागरिक एकता मंच ने 25 अगस्त को वन विभाग कार्यालय घेराव की घोषणा की,और अब जय सोनपाकर ने मजदूरी भुगतान और मस्टर रोल की जांच का नया मुद्दा उठाकर पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है।

मशीनें चलीं तो मजदूर कहां से आए?

अधिवक्ता जय सोनपाकर का कहना है कि यदि निर्माण कार्यों में वास्तव में जेसीबी और ट्रैक्टर का उपयोग हुआ है,तो यह जांच का विषय है कि सरकारी अभिलेखों में दर्ज मजदूर कौन हैं,उन्होंने कहा कि वन विभाग की अधिकांश योजनाओं का उद्देश्य केवल निर्माण कराना नहीं,बल्कि स्थानीय ग्रामीणों और आदिवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना भी है,यदि कार्य मशीनों से हुआ, तो फिर–मस्टर रोल किसके नाम से भरे गए? मजदूरी किसे दी गई? क्या जिन लोगों के नाम दर्ज हैं, उन्होंने वास्तव में काम किया? यदि नहीं किया, तो भुगतान किस आधार पर हुआ? जय सोनपाकर का कहना है कि इन प्रश्नों का उत्तर केवल विभागीय स्पष्टीकरण से नहीं,बल्कि दस्तावेजी और वित्तीय जांच से ही मिल सकता है।

'फर्जी मस्टर रोल और भूतहा मजदूरों' की आशंका...

जय सोनपाकर ने आरोप लगाया कि यदि मशीनों से कराए गए कार्यों के बावजूद मजदूरी का भुगतान दिखाया गया है, तो यह फर्जी मस्टर रोल का मामला हो सकता है,उन्होंने कहा कि कई सरकारी योजनाओं में पहले भी फर्जी मस्टर रोल और काल्पनिक मजदूरों के नाम पर भुगतान के आरोप सामने आते रहे हैं,इसलिए इस मामले में भी निष्पक्ष जांच आवश्यक है,उनका कहना है कि यदि विभाग ने नियमों के अनुरूप कार्य कराया है तो जांच से उसका पक्ष भी स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन यदि अनियमितता हुई है तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।

समिति ने रखीं तीन बड़ी मांगें...

1. **मशीन बनाम मजदूर की जांच**-समिति का कहना है कि प्रत्येक निर्माण स्थल का भौतिक सत्यापन किया जाए, जहां मशीनों से कार्य हुआ हो,वहां मस्टर रोल में दर्ज मजदूरों का मिलान कराया जाए।
2. **बैंक खातों की जांच**-समिति ने मांग की है कि जिन बैंक खातों में मजदूरी का भुगतान हुआ है,उनका सत्यापन कराया जाए,यह देखा जाए कि खाते वास्तविक मजदूरों के हैं या नहीं,भुगतान किस तिथि को हुआ,भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति ने वास्तव में कार्य किया या नहीं,यदि आवश्यक हो तो लाभार्थियों का स्थल पर जाकर सत्यापन कराया जाए।
3. **तकनीकी एवं वित्तीय ऑडिट**-समिति का कहना है कि सभी निर्माण कार्यों की मेजरमेंट बुक (एमबी),प्रशासनिक स्वीकृति,तकनीकी स्वीकृति,भुगतान आदेश, गुणवत्ता परीक्षण,उपयोगिता प्रमाण पत्र,की स्वतंत्र जांच कराई जाए,उन्होंने सुझाव दिया कि यह जांच जिले से बाहर के तकनीकी विशेषज्ञों की टीम द्वारा कराई जाए, ताकि निष्पक्षता पर कोई सवाल न उठे।

अब सबसे बड़ा सवाल

यदि जांच में यह सामने आता है कि निर्माण कार्य वास्तव में मशीनों से हुए और उसी अवधि में मजदूरी के नाम पर बड़ी राशि का भुगतान भी दर्ज है, तो यह केवल निर्माण गुणवत्ता का मामला नहीं रहेगा,बल्कि सरकारी धन के उपयोग और अभिलेखों की सत्यता से जुड़ा गंभीर प्रशासनिक प्रश्न बन जाएगा,दूसरी ओर,यदि जांच में यह स्पष्ट होता है कि मशीनों का उपयोग नियमानुसार हुआ और मजदूरी भुगतान भी वास्तविक श्रमिकों को किया गया,तो इससे विभाग का पक्ष भी सामने आएगा,फिलहाल पूरा मामला निष्पक्ष जांच की मांग के केंद्र में है और अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि वन विभाग और शासन इन आरोपों पर क्या कार्रवाई करते हैं।

129 दिन तक ड्यूटी से गायब रहने वाला आरक्षक सेवा से बर्खास्त

विभागीय जांच में आरोप सिद्ध,पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल ने जारी किया सेवा से पृथक करने का आदेश

-संवाददाता-
सूरजपुर,31 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

जिला पुलिस सूरजपुर ने अनुशासनहीनता के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए 129 दिनों तक बिना अनुमति ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले आरक्षक अमरदीप विश्वकर्मा को सेवा से पृथक कर दिया है। विभागीय जांच में आरोप सिद्ध होने के बाद पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल (भा.पु.से.) ने यह आदेश जारी किया। साथ ही अनुपस्थिति की अवधि को 'कार्य नहीं,वेतन नहीं'के सिद्धांत के तहत अवैतनिक घोषित किया गया है।

बंदी पेशी ड्यूटी से गायब हुआ आरक्षक-पुलिस विभाग के अनुसार आरक्षक अमरदीप विश्वकर्मा की ड्यूटी 25 जून 2025 को बंदी पेशी के लिए लगाई गई थी, लेकिन वह उसी दिन से बिना सक्षम अनुमति और बिना विभाग को नियमानुसार सूचना दिए ड्यूटी से अनुपस्थित हो गया,विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार वह 25 जून 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक लगातार 129 दिनों तक ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हुआ।

कई नोटिस के बावजूद नहीं हुआ उपस्थित-अनुपस्थिति के दौरान विभाग ने संबंधित आरक्षक को कई बार नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण देने और तत्काल ड्यूटी पर लौटने के निर्देश दिए, इसके बावजूद वह नियत समय में उपस्थित नहीं हुआ,जिसके बाद उसके विरुद्ध विभागीय जांच प्रारंभ की गई।

जांच में आरोप हुए प्रमाणित-विभागीय जांच के दौरान आरक्षक को आरोप पत्र जारी कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया,जांच अधिकारी ने दस्तावेजों,साक्ष्यों और गवाहों के बयान का परीक्षण किया,जांच में यह सामने आया कि आरक्षक ने उपचार संबंधी कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए, लेकिन लंबी अवधि तक अनुपस्थित रहने के दौरान विभाग को नियमानुसार कोई लिखित सूचना या अवकाश स्वीकृति के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं किया, जांच रिपोर्ट में इसे पुलिस जैसे अनुशासित बल में गंभीर अनुशासनहीनता और कर्तव्य के प्रति लापरवाही माना गया।

पूर्व सेवा रिकॉर्ड भी रहा असंतोषजनक-विभागीय जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित आरक्षक का पूर्व सेवा रिकॉर्ड भी संतोषजनक नहीं था, सेवा अभिलेखों के अनुसार वह पहले भी कई बार अनाधिकृत अनुपस्थिति के मामलों में विभागीय कार्रवाई का सामना कर चुका था,उस पर पूर्व में अवैतनिक अवधि घोषित करने, वेतनवृद्धि रोकने सहित कई छोटी और बड़ी विभागीय सजाएं दी जा चुकी थीं। इसके बावजूद उसके व्यवहार और कार्यशैली में अपेक्षित सुधार नहीं आया।

31 जुलाई को जारी हुआ सेवा से पृथक करने का आदेश-विभागीय जांच में आरोप सिद्ध होने के बाद पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल ने 31 जुलाई 2026 को आरक्षक अमरदीप विश्वकर्मा को सेवा से पृथक करने का आदेश जारी किया। साथ ही 25 जून 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक की 129 दिनों की अनुपस्थिति अवधि को छत्तीसगढ़ पुलिस नियमों के अनुसार अवैतनिक घोषित किया गया।

अनुशासनहीनता पर सख्त संदेश-पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल ने कहा कि पुलिस विभाग एक अनुशासित बल है,जहां प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी से कर्तव्यनिष्ठा,जवाबदेही और अनुशासन की अपेक्षा की जाती है, बिना अनुमति ड्यूटी से अनुपस्थित रहना।

सोनहत में सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय का शुभारंभ,संस्कार और राष्ट्र निर्माण आधारित शिक्षा की नई शुरुआत

विद्या भारती के प्रांतीय संगठन मंत्री देव नारायण साहू और विधायक रेणुका सिंह ने किया शुभारंभ,भारतीय संस्कृति आधारित शिक्षा पर दिया जोर

वक्ताओं ने कहा...विद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र नहीं,बल्कि चरित्र निर्माण और राष्ट्रभावना की पाठशाला

-संवाददाता-
सोनहत,31 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

भारतीय संस्कृति,संस्कार और राष्ट्र निर्माण की भावना पर आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय, सोनहत का भव्य शुभारंभ गरिमामय एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ,समारोह में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, अभिभावकों तथा बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही,शुभारंभ के अवसर पर वक्ताओं ने शिक्षा के साथ भारतीय संस्कृति,नैतिक मूल्यों और चरित्र निर्माण के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला तथा विद्यालय को क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक उपलब्धि बताया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं विद्या भारती के प्रांतीय संगठन मंत्री देव नारायण साहू ने कहा कि विद्या भारती की शिक्षा व्यवस्था केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं है,बल्कि उसका उद्देश्य ऐसे विद्यार्थियों का निर्माण करना है,जो संस्कारित, अनुशासित,चरित्रवान और राष्ट्रभक्ति की भावना से ओत-प्रोत हों,उन्होंने कहा कि आज के समय में आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कृति,नैतिक मूल्यों और जीवनोपयोगी संस्कारों का समावेश अत्यंत आवश्यक है, यदि शिक्षा केवल रोजगार प्राप्त करने का माध्यम बन जाए और उसमें संस्कारों का अभाव हो,तो उसका उद्देश्य अधूरा रह जाता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

रोजगार ही नहीं,श्रेष्ठ नागरिक बनाना भी शिक्षा का उद्देश्य : रेणुका सिंह-कार्यक्रम की संरक्षक सदस्य एवं क्षेत्रीय विधायक रेणुका सिंह ने कहा कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल नौकरी या रोजगार प्राप्त करना नहीं,बल्कि ऐसे नागरिक तैयार करना है जो अपने परिवार,समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पित हों,उन्होंने कहा कि भारतीय शिक्षा परंपरा सदैव ज्ञान के साथ संस्कारों पर आधारित रही है,सरस्वती शिशु मंदिर जैसे विद्यालय बच्चों में अनुशासन, नैतिकता, सेवा और राष्ट्रभक्ति की भावना विकसित करते हैं,उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह विद्यालय आने वाले वर्षों में सोनहत क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण एवं संस्कारयुक्त शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनेगा।

विद्यालय केवल भवन नहीं, संस्कारों की पाठशाला-विद्यालय समिति के अध्यक्ष रामप्रताप सिंह ने कहा कि सरस्वती शिशु मंदिर केवल शिक्षा देने वाला संस्थान नहीं, बल्कि संस्कार, अनुशासन और राष्ट्रभावना का केंद्र है,यहां विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास के साथ-साथ उनके नैतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास पर भी समान रूप से ध्यान दिया जाएगा,उन्होंने अभिभावकों से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा से जोड़ें,जो उन्हें केवल सफल नहीं, बल्कि एक अच्छा और जिम्मेदार नागरिक भी बनाए।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है विद्यालय

विद्यालय के व्यवस्थापक प्रकाश रजवाड़े ने कहा कि विद्यालय आधुनिक शिक्षा और भारतीय संस्कारों का समन्वय करते हुए विद्यार्थियों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है,उन्होंने कहा कि विद्यालय में अनुशासित शिक्षण व्यवस्था,योग्य शिक्षकों का मार्गदर्शन और संस्कार आधारित गतिविधियों के माध्यम से बच्चों के सर्वांगीण विकास का प्रयास किया जाएगा, उन्होंने अभिभावकों से अधिक से अधिक बच्चों का प्रवेश कराकर इस शिक्षा अभियान का हिस्सा बनने की अपील की।

विद्या भारती की शिक्षा पद्धति की बताई विशेषताएं

संभाग समन्वयक राजेश मिश्रा ने विद्या भारती की संस्कार आधारित शिक्षा प्रणाली की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल परीक्षा में सफलता प्राप्त करना नहीं,बल्कि राष्ट्रनिष्ठ, सेवाभावी, आत्मविश्वासी और चरित्रवान व्यक्तित्व का निर्माण करना है,उन्होंने बताया कि विद्या भारती के विद्यालयों में विद्यार्थियों के शारीरिक,मानसिक,बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास पर समान रूप से बल दिया जाता है, जिससे वे समाज और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभा सकें।

प्रधानाचार्य ने बताई विद्यालय की भावी कार्ययोजना

कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य दीपक पांडेय ने सभी अतिथियों,अभिभावकों और क्षेत्रवासियों के प्रति आभार व्यक्त किया,उन्होंने विद्यालय की भावी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि संस्था का उद्देश्य विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ संस्कार,अनुशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना से जोड़ना है,उन्होंने कहा कि विद्यालय में शिक्षा के साथ खेल,योग,सांस्कृतिक गतिविधियों और व्यक्तित्व विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा,ताकि बच्चे जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें।

बड़ी संख्या में शामिल हुए अभिभावक और गणमान्य नागरिक

कार्यक्रम में संरक्षक सदस्य सिद्धि विनायक पाण्डेय,विद्यालय समिति के अध्यक्ष रामप्रताप सिंह,व्यवस्थापक प्रकाश रजवाड़े, प्रधानाचार्य दीपक पांडेय,संभाग समन्वयक राजेश मिश्रा सहित बड़ी संख्या में अभिभावक, शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता एवं क्षेत्रवासी उपस्थित रहे, समारोह का समापन माँ सरस्वती एवं भारत माता के जयघोष तथा राष्ट्रगान के साथ हुआ,उपस्थित लोगों ने विश्वास व्यक्त किया कि सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय आने वाले समय में सोनहत क्षेत्र में संस्कारयुक्त एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का एक मजबूत केंद्र बनकर उभरेगा।

CMYK

श्रीदेवी की जानी दुश्मन थी 80 के दशक की एक्ट्रेस

राजेश खन्ना ने सुलह कराने के लिए दोनों को किया था कमरे में बंद

80 दशक की एक टॉप एक्ट्रेस के साथ श्रीदेवी की नहीं बनती थी। उस वक्त राजेश खन्ना ने उनकी दोस्ती कराने के लिए एक पैतरां अपनाया था।

श्रीदेवी का 80दशक के दौर की टॉप एक्ट्रेस के साथ छत्तीस का आंकड़ा था। दोनों ने साथ में कई फिल्में कीं, लेकिन फिर भी उनकी नहीं बनी। एक बार राजेश खन्ना ने उन्हें एक कमरे में लॉक भी कर दिया था। मगर यह ट्रिक भी उनके बीच सुलह नहीं करा पाई।

दरअसल,जिस दौर में श्रीदेवी टॉप पर थीं, उसी दौरान एक और एक्ट्रेस की फिल्मी गलियारों में बड़ी डिमांड थीं। यह एक्ट्रेस जया प्रदा हैं। 70, 80 औक 90 के दशक में काम कर चुकीं जया प्रदा,श्रीदेवी की कॉम्पटीटर थीं।

ऑफ-स्क्रीन जया-श्रीदेवी नहीं थे दोस्त

जया प्रदा और श्रीदेवी ने साथ में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। ऑन-

स्क्रीन उनकी जोड़ी हिट थी,लेकिन ऑफ-कैमरा दोनों नजरें मिलाना भी पसंद नहीं करते थे। उनकी राइवलरी को खत्म करने की राजेश खन्ना की कोशिश भी काम नहीं आई थी। खुद जया प्रदा ने इससे जुड़ा किस्सा शेयर किया था।

जया-श्रीदेवी के बीच रहता था कॉम्पटीशन

2021 में इंडियन आइडल 12 में जया ने श्रीदेवी के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात की थी। उन्होंने बताया था-

स्क्रीन पर परफेक्ट बहनें बनने के बाद भी हमारी कभी एक-दूसरे से नजरें नहीं मिलीं। हम दोनों के बीच हमेशा कॉम्पटीशन रहता था, चाहे वो ड्रेस हो या डांस। जब भी हम मिलते थे, डायरेक्टर या एक्टर सेट पर हमारा परिचय कराते थे। हम बस एक-दूसरे को नमस्ते करते और आगे बढ़ जाते थे।

एक कमरे में लॉक हो गई थीं जया और श्रीदेवी

जया प्रदा ने श्रीदेवी से जुड़ा एक किस्सा भी शेयर किया था। उन्होंने बताया था कि एक बार राजेश खन्ना और जीतेंद्र ने दोनों के बीच बात कराने के लिए उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया था। एक्ट्रेस ने कहा था-

मुझे आज भी याद है कि मकसद की शूटिंग के दौरान,जीतू जी और राजेश खन्ना जी ने हम दोनों को एक घंटे के लिए एक मेकअप रूम में बंद कर दिया था क्योंकि उन्हें लगा कि हम एक-दूसरे से बात करना शुरू कर देंगी,लेकिन हमने एक शब्द भी नहीं कहा। आखिरकार बॉलीवुड के सुपरस्टार्स ने हार मान ली।

जया प्रदा ने यह भी कहा था कि जब 2018 में श्रीदेवी का निधन हुआ था, तब उन्हें इस बात का पछतावा हुआ था कि वह अपनी को-स्टार के साथ दोस्ती नहीं बना पाई। उन्होंने कहा था कि वह उन्हें बहुत मिस करती हैं।

रानी पिंक सूट में शहनाज गिल ने ढाया कहर

वायरल एथनिक फोटोशूट ने जीता फैंस का दिल

बॉलीवुड और पंजाबी इंडस्ट्री की चहेती अदाकारा शहनाज गिल अपने स्टाइल स्टेटमेंट और गजब के ट्रांसफॉर्मेशन से हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं। हाल ही में शहनाज ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक नया एथनिक फोटोशूट पोस्ट किया है, जो देखते ही देखते इंटरनेट पर आग की तरह वायरल हो गया है।इस लेटेस्ट फोटोशूट में शहनाज ने गहरे रानी पिंक कलर का बेहद खूबसूरत एथनिक सूट कैरी किया है। उनके इस आउटफिट को बहुत ही बारीकी से डिजाइन किया गया है। कुर्ती के योक पर गोल्डन थ्रेडवर्क, बारीक गोटा-पत्ती और जटिल जरदोजी वर्क के साथ-साथ शानदार मिरर और सेक्विन वर्क किया गया है।कुर्ती के डीप-नेकलाइन और स्लीव्स के किनारों पर लगे लटकन-मोती इस ड्रेस को एक रॉयल और हेरिटेज लुक दे रहे हैं। इसके साथ उन्होंने मैचिंग एम्ब्रॉयडरी वाली स्ट्रेट-फिट एंकल लेंथ पैंट और नेट का एक खूबसूरत शीर दुपट्टा पेयर किया है, जो उनके पूरे लुक में एलिगेंस का तड़का लगा रहा है।शहनाज गिल अपने ने मेकअप को बेहद सिंपल और सटल रखा है। उन्होंने लाउड कलर्स को छोड़कर न्यूड-ग्लॉसी लिप्स, न्यूड आईशैडो, मस्कारा से सजी पलकें और हल्का सा ब्लश ऑन चुना है, जो उनके नेचुरल फीचर्स को बखूबी उभार रहा है।हेयरस्टाइल की बात करें तो शहनाज ने अपने सिग्नेचर स्टाइल को अपनाते हुए बालों को मिडल-पार्टिंग के साथ सॉफ्ट वेवी लुक दिया है। उनके खुले काले बाल कंधों पर लहराते हुए उनके चेहरे के कट को बेहद खूबसूरती से फ्रेम कर रहे हैं।शहनाज गिल का यह फोटोशूट किसी लग्जरियस इनडोर स्टूडियो का लग रहा है, जहां वह एक आलीशान विंटेज आर्मचेयर पर बैठकर बेहद दिलकश अंदाज में पोज दे रही हैं। तस्वीरों में शहनाज का आत्मविश्वास और उनका सेक्सी पोस्चर साफ झलक रहा है।कभी वह चेयर पर रॉयल अंदाज में पीछे की ओर झुककर कैमरे में इंटेंस लुक दे रही हैं, तो कभी अपनी थिक-बॉर्डर वाली पैंट और गोल्डन हील्स को फ्लॉन्ट करते हुए फ्रंट पोज दे रही हैं। एक तस्वीर में वह अपने सिर को हाथों से थामे हुए गहराई से सोचती नजर आ रही हैं, जो उनके फैंस को काफी आकर्षित कर रहा है।शहनाज के चेहरे का ग्लो और उनके सिजलिंग फेशियल एक्सप्रेशंस इस पारंपरिक आउटफिट में भी बोल्डनेस और ग्लैमर का परफेक्ट फ्यूजन पेश कर रहे हैं। शहनाज की इन तस्वीरों पर कमेंट बॉक्स में फैंस बॉम्बशेल, रॉयल क्वीन और ब्यूटी इन पिंक जैसे कमेंट्स की बौछार कर रहे हैं। कुछ ही घंटों में इस पोस्ट पर लाखों लाइक्स आ चुके हैं।

राशी खन्ना ने रजनीकांत से मिले खास तोहफे के बारे में खुशी ज़ाहिर की

एक्ट्रेस राशी खन्ना, जिन्हें आखिरी बार द साबरमती रिपोर्ट में देखा गया था, को तमिल सुपरस्टार रजनीकांत से एक खास तोहफ़ा मिला। शुक्रवार को एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वह कैमरे से बात कर रही थीं। वीडियो में उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें अपनी आने वाली फ़िल्म धर्मन के सेट पर थलाइवा के साथ काम करते हुए लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स नाम का एक बहुत अच्छा तोहफ़ा मिला

एक्ट्रेस ने कहा कि इस किताब ने उन्हें अपने अंदर झांकने और यह समझने का मौका दिया कि लोगों के बीच इतना गहरा अलगाव क्यों है। उन्होंने कहा,लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स% किताब मुझे बहुत खास तरीके से मिली। मैं धर्मन के सेट पर रजनीकांत सर के साथ शूटिंग कर रही थी। बातचीत के दौरान, हम आध्यात्मिकता के बारे में बात करने लगे। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैंने यह किताब पढ़ी है; मैंने नहीं पढ़ी थी। दो दिन बाद, वह इसकी एक कॉपी लाए और मुझे तोहफ़े में दी। मैं पिछले कुछ हफ़्तों से इसे ध्यान से पढ़ रही हूँ क्योंकि उन्होंने यह भी कहा था कि वह मुझसे इस पर सवाल पूछेंगे। वैसे भी, मुझे यह किताब बहुत पसंद आ रही है, और कभी-कभी मुझे कोई ऐसा पन्ना मिल जाता है जो मुझे सोचने पर मजबूर कर देता है।अपनी इस किताब से मिली मुख्य सीख के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, मैंने इससे यह सीखा कि हममें से बहुत से लोग अलग-थलग क्यों महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि हमने रातों-रात खुद को खो दिया है,बल्कि इसलिए है क्योंकि हमने सालों तक कोई और बनने की कोशिश की है। और शायद इसीलिए खामोशी इतनी तेज़ महसूस हो सकती है। क्योंकि बिना किसी भटकाव के, आप आखिरकार सिर्फ़ अपने साथ होते हैं।इस बीच, रजनीकांत और राशी खन्ना की फ़िल्म धर्मन अपनी घोषणा के समय से ही चर्चा में है। अश्वथ मारिमुथु द्वारा निर्देशित यह फ़िल्म तमिल प्रोडक्शन की सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली फ़िल्मों में से एक है।

रामायण ट्रेलर देख बोले रामानंद सागर के पोते,रणबीर से उम्मीद

नितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण' को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। करीब 4000 करोड़ रुपये के बजट वाली इस पौराणिक फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा तेज हो गई है। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं,जबकि साई पल्लवी माता सीता और यश रावण के किरदार में नजर आएंगे। अब इस फिल्म को लेकर 1987 में आए ऐतिहासिक टीवी सीरियल 'रामायण' के निर्माता रामानंद सागर के पोते शिव सागर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। शिव सागर ने रणबीर कपूर स्टारर 'रामायण' के ट्रेलर की तारीफ करते हुए कहा कि फिल्म का विजुअल अनुभव और पूरी स्टारकास्ट काफी प्रभावशाली लग रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि दर्शक रणबीर कपूर को भगवान राम के किरदार में स्वीकार करेंगे और उन्हें इस भूमिका के लिए शुभकामनाएं दीं। शिव सागर ने एक इंटरव्यू में कहा कि शुरुआती प्रमोशनल कंटेंट देखने के बाद उन्हें लगा था कि फिल्म के ग्राफिक्स और विजुअल इफेक्ट्स बजट के हिसाब से उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। हालांकि, ट्रेलर देखने के बाद उनकी राय बदल गई। उन्होंने कहा कि ट्रेलर और कलाकारों को देखने के बाद वह काफी प्रभावित हुए हैं।

आमिर खान ने राजकुमार संतोषी से सनी देओल के लिए कहा था कुछ ऐसा,भौचक्का रह गए थे निर्देशक

राजकुमार संतोषी और सनी देओल की सफल जोड़ी पर आमिर खान ने एक दिलचस्प टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने सनी के लिए लिखी स्क्रिप्ट में खुद को कास्ट करने की बात कही। कुछ निर्देशक और कलाकार की जोड़ी ऐसी होती है, जो जब भी साथ आते हैं कमाल करते हैं। निर्देशक राजकुमार संतोषी और सनी देओल की जोड़ी ऐसी रही है, जिन्होंने घायल,घातक और दामिनी जैसी हिट फिल्में दी हैं।

बॉलीवुड में हिट है आमिर और संतोषी की जोड़ी

राजकुमार भी मानते हैं कि उन्होंने जो फिल्में लिखीं और बनाई,उसमें उनका बेस्ट काम सनी के साथ रहा है। यही कारण है अभिनेता आमिर खान ने राजकुमार से कहा कि उन्हें फिल्में पहले सनी के लिए लिखनी चाहिए,फिर सनी को निकालकर उन्हें ले लेना चाहिए। दरअसल,आमिर फिल्म बंटवारा 1947 के निर्माता है,जिसका निर्देशन राजकुमार ने किया है और सनी फिल्म के मुख्य अभिनेता है।

आमिर खान ने क्यों कही थी ऐसी बात?

एक किस्सा सुनाते हुए राजकुमार कहते हैं कि आमिर मुझे आज भी कहते हैं कि तुम सनी के लिए जब भी काम करते हो या कुछ भी

लिखते हो, चाहे वह स्क्रिप्ट हो या डायलाग हो,बहुत अच्छा काम करते हैं। एक काम करो, स्क्रिप्ट सनी के लिए लिखना, लेकिन फिर उन्हें निकाल मुझे उसमें कास्ट कर लेना, तब अच्छी फिल्म बनेगी। खैर,मेरे लिए सनी साहब हिम्मत का सबसे बड़ा स्रोत हैं। सनी को मुझ पर पूरा भरोसा है, फिर चाहे दामिनी फिल्म हो या बंटवारा, वह मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। मैंने इस फिल्म के लिए भी एक ही बार नरेशन दिया था। उन्होंने कहा कि यह फिल्म करनी है।

कोई फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए नहीं था तैयार

16 साल से हम इस फिल्म को बनाने में लगे हैं,एक इंच भी इधर से उधर नहीं हिले हैं। गदर 2 के बाद उन्होंने कहा की बंटवारा 1947 पर काम शुरू करते हैं। आगे राजकुमार कहते हैं कि यह फिल्म मेरे लिए किसी तपस्या से कम नहीं है। मैं इस फिल्म को साल 2010 से बनाना चाहता हूं,जब मैंने साल 2009 में पहली बार वह नाटक (जिस लाहौर नइ देख्या ओ जम्याइ नइ) पढ़ा था। साल 2010 से फिल्म बनाने की कोशिश में हूं,16 साल हो गए हैं। जब सनी को फिल्म सुनाई थी,तब वह भी ऊर्जा से भरपूर थे कि यह फिल्म बनानी है। हम दोनों के 16 सालों से प्रयास कर रहे हैं कि फिल्म बन जाए, लेकिन जैसे हम इसे बनाना चाहते थे,वैसे किसी का कहीं से सपोर्ट मिला नहीं। फिर आमिर ने कहानी कही सुनी, उन्हें पसंद आई और उन्होंने हिम्मत बढ़ाई की फिल्म बनानी ही है।

खेल समाचार

अमित शाह ने मेडल जीतने वाले प्रदर्शन के लिए सीमा और लवप्रीत को दी बधाई

ग्लासगो,31 जुलाई 2026। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में मेडल जीतने वाले एथलीट सीमा कालीरामना और वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंह को बधाई दी है। सीमा ने महिलाओं के डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज़ मेडल जीतकर भारत के मेडल टैली में एक और मेडल जोड़ा,और लवप्रीत ने पुरुषों के 110+ किग्रा वेटलिफ्टिंग इवेंट में कुल 388 किग्रा वज़न उठाकर सिल्वर मेडल जीता। अमित शाह ने सीमा के प्रदर्शन की तारीफ़ की और कहा कि खेल के प्रति उनके समर्पण और अथक प्रयासों की वजह से उन्हें पोडियम पर जगह मिली है। उन्होंने कहा, बहुत बढ़िया,सीमा। खेल के प्रति आपके समर्पण और अथक प्रयासों ने आपको कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिलाओं के डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज़ मेडल के साथ पोडियम तक पहुँचाया है। आपकी कड़ी मेहनत को और सफलता मिले।

शाह ने कहा कि लवप्रीत के प्रदर्शन ने भारत का मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा,कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों के 110+ किग्रा वर्ग में सिल्वर मेडल जीतने पर लवप्रीत सिंह को बधाई। अपनी क्षमता के शानदार प्रदर्शन के साथ

आपकी जीत ने भारत के गौरव को नई ऊँचाई पर पहुँचाया है। आपको और शक्ति मिले। सीमा ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिलाओं के डिस्कस थ्रो फ़ाइनल में यादगार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज़ मेडल जीता।

जमैका की सामंथा हॉल ने 61.66 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता,जबकि कनाडा की जूलिया टंक्स ने 60.67 मीटर के साथ सिल्वर मेडल जीता,और सीमा 58.65 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। लवप्रीत ने अपने दूसरे क्लीन एंड जर्क प्रयास में सफलतापूर्वक 212 किग्रा वज़न उठाकर गोल्ड मेडल पर अपनी पकड़ मज़बूत की, जिससे उनका कुल वज़न कॉमनवेल्थ गेम्स के रिकॉर्ड 388 किग्रा तक पहुँच गया।

कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के दो और मेडल पक्के

कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के जुडोकाओं ने कमाल करते हुए दो मेडल पक्के कर लिए हैं...हर्ष सिंह मेंस 60 किलो ग्राम फाइनल में पहुंचकर कम से कम सिल्वर मेडल पक्का कर चुके हैं,वहीं अष्मिता डे ने महिलाओं के 48 किलो ग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बनाकर पदक पक्का कर दिया है...

नई दिल्ली, 31 जुलाई 2026। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए जुडो के मैदान से बेहद शानदार खबर सामने आई है। भारतीय खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए देश के लिए दो पदक पक्के कर लिए हैं। महिला वर्ग में अष्मिता डे ने रोमांचक जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह बनाई, तो वहीं मेंस कैटेगरी में हर्ष सिंह ने अपने प्रतिद्वंद्वी को पछाड़कर सीधे फाइनल में प्रवेश कर लिया है।

हर्ष सिंह का फाइनल में धमाका, सिल्वर पदक पक्का

मेंस के 60 किलो ग्राम वर्ग में हर्ष सिंह ने रिंग में उतरते ही एकतरफा खेल दिखाया। सेमीफाइनल मुकाबले में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पेड्रो कार्लोस एंटुन नेटो को 10-0 से करारी शिकस्त दी। मैच की शुरुआत से ही हर्ष ने बढ़त बनाए रखी और एक सटीक थ्रो के जरिए निर्णायक अंक हासिल किया। इस शानदार जीत के साथ ही हर्ष ने फाइनल में जगह बना

स्कॉटलैंड की समर शॉ को एक सांस रोक देने वाले मुकाबले में हराया। दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला और निर्धारित समय तक स्कोर बराबर रहा। इसके बाद मैच गोल्डन स्कोर में गया। कुल 6 मिनट 27 सेकंड की मैराथन फाइट के बाद अष्मिता ने शानदार थ्रो लगाकर जीत हासिल की और भारत का पहला जुडो पदक पक्का करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया।

गोल्ड मेडल मुकाबलों पर टिकीं देश की निगाहें

इन दोनों युवा खिलाड़ियों के असाधारण प्रदर्शन ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय दल का उत्साह काफी बढ़ा दिया है। अब सभी की निगाहें हर्ष सिंह के गोल्ड मेडल मैच पर टिकी होंगी, वहीं अष्मिता डे भी अपने सेमीफाइनल मुकाबले को जीतकर स्वर्ण पदक की रेस में आगे बढ़ने के इरादे से मैदान में उतरेंगी। वहीं हर्ष गोल्ड मेडल से सिर्फ एक कदम दूर हैं।

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा,छ0ग0

रा.प्र.क्र./ब-121/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक विनोद कुमार गुप्ता आ0 पृथ्वीनाथ साव निवासी रिंग रोड नमनाकला तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की व्यपवर्तित भूमि ग्राम गंगापुरखुर्द स्थित भूमि खसरा नंबर 248/5 रकबा 0.062 हे0 भूमि मेसे अपने अंश की भूमि को अनावेदक अंकित कुमार गुप्ता आ0 विनोद कुमार गुप्ता निवासी रिंग रोड नमनाकला तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के पास हक त्याग करने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र श्रीमान कलेक्टर महोदय सरगुंजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो जांच एवं प्रतिवेदनार्थ इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 10.08.2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है । समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा ।

आज दिनांकः- 17/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — तहसीलदार अंबिकापुर,सरगुजा

न्यायालय नजूल अधिकारी सूरजपुर,जिला-सूरजपुर,छ0ग0

रा.प्र.क्र./अ-20(1)/2025-26

ईश्तहार

आगामी तिथि 3/9/2026

इस सार्वजनिक ईश्तहार के जरिये सर्व साधारण आम जनता/संस्था/ विभाग को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है आवेदक तीन कौडी चटर्जी. पिता ललित मोहन चटर्जी निवासी वार्ड क्र 05 साहूपारा सूरजपुर थाना व तहसील सूरजपुर जिला-सूरजपुर छ0ग0 द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपने स्वामित्व व अधिपत्य की नजूल भूमि प्लाट नम्बर 2010/2 रकबा क्रमशः 2613 वर्गफीट भूमि का लीज दिनांक 31/03/2026 को समाप्त होने से आगामी 30 वर्ष के लिए लीज नवीनीकरण कराये जाने हेतु अनुरोध मा. न्यायालय अपर कलेक्टर सूरजपुर के समक्ष किया गया है। जो अग्रिम कार्यवाही हेतु एतद् न्यायालय को प्राप्त हुआ है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन लंबित है।

अतः इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति/संस्था/विभाग को कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अभिभाषक/लीगल एजेंट के माध्यम से अपना दावा/आपत्ति दिनांक 3/9/2026 को न्यायालयीन अवधि में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

आज दिनांक 30/7/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया ।

सील — नजूल अधिकारी ,सूरजपुर

नाम परिवर्तन सूचना

मैं दीपक कुमार गुप्ता पिता श्री नरेश प्रसाद गुप्ता आयु 31 वर्ष निवासी नवापारा लुर्गीखुर्द पो./ थाना रनहत तहसील दौरा-कोचली जिला बलरामपुर (छ.ग.)।

यह कि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम आरची गुप्ता आ. दीपक कुमार गुप्ता हैं। जो कि वास्तविक और सही है आरची गुप्ता (AARCHI GUPTA) के नाम से जाना जाये जो कि सही और वास्तविक हैं। मेरी पुत्री आरची गुप्ता की शैक्षणिक प्रमाण पत्र में यही नाम दर्ज हैं परन्तु आधार कार्ड में त्रुटिवश आचि हो गया है जो कि गलत हैं। मेरी पुत्री का आधार कार्ड क्र. 737616873037 है। उसका आधार कार्ड में वास्तविक नाम आरची गुप्ता अंकित किया जाय।

शपथग्रहिता
दीपक कुमार गुप्ता

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,छ0ग0

ईश्तहार

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक प्रभा गुप्ता आ0 गोपाल गुप्ता निवासी देवीगंज,अम्बिकापुर (थाना अम्बिकापुर तहसील ने कराया है कि आवेदक के .अपने पिता स्व0 जमनाथ साव आ0 सेवक राम की दिनांक 10/01/1975 को स्थान अम्बिकापुर में हुई है। आवेदक के मृत्यू उपरांत मृत्यू का पंजीयक नहीं कराया गया है । अतः प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होने पर यह आवेदन पेश किया गया है ।

उक्त संबंध में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो ईश्तहार प्रकाशन से 15 दिवस तक न्यायलय में उपस्थित होकर अपना दावा/ आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। समय-सीमा के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

आज दिनांक 31/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालीन मुद्रा से जारी ।

सील — तहसीलदार अंबिकापुर,सरगुजा

अंकुश पंघाल फाइनल में पहुंचे

ग्लासगो,31 जुलाई 2026। भारतीय बॉक्सर अंकुश पांगल ने शुक्रवार को सेमीफाइनल में कनाडा के जोशुआ ओफ़ोरी पर एकतरफा और सर्वसम्मत जीत हासिल करके कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के पुरुषों के 80 किग्रा फ़ाइनल में जगह बनाई। पिछले राउंड में सेशेल्स के जेड मिकॉक को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचे अंकुश ने पूरे मुकाबले के दौरान शानदार स्पीड, सटीकता और संयम दिखाया और भारत के लिए कम से कम सिल्वर मेडल पक्का किया।

भारतीय खिलाड़ी ने पहले राउंड में मज़बूत शुरुआत की,साफ़ कॉम्बिनेशन और असरदार पंच लगाकर ओफ़ोरी पर बढ़त बनाई और सभी पांच जजों ने यह राउंड उनके पक्ष में दिया। ओफ़ोरी ने दूसरे राउंड में आक्रामकता बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अंकुश सटीक पंचों के साथ हावी रहे। सिर के पिछले हिस्से पर प्रहार करने के कारण कनाडाई खिलाड़ी का एक पॉइंट भी कट गया,जिससे अंकुश का

दबदबा बना रहा और उन्होंने एक और राउंड 5-0 से अपने नाम किया।

आखिरी राउंड में,ओफ़ोरी ने आक्रामक हमलों के साथ वापसी करने की कोशिश की, लेकिन अंकुश संयमित रहे और अच्छा बचाव करते हुए ज़रूरी पंच भी लगाए। भारतीय बॉक्सर ने सर्वसम्मत फ़ैसले से मुकाबला जीता और गोल्ड मेडल के मुकाबले में अपनी जगह पक्की की।अंकुश की जीत कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के मज़बूत बॉक्सिंग अभियान को और आगे बढ़ाती है, क्योंकि भारतीय दल ग्लासगो में शानदार प्रदर्शन जारी रखे हुए है। इससे पहले दिन में, प्रीति पंवार ने ज़ाम्बिया की कैथरीन म्वापे पर एकतरफा और सर्वसम्मत जीत के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के महिलाओं के 54 किग्रा फ़ाइनल में जगह बनाई।

भारत ने अब तक कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 17 मेडल जीते हैं, जिनमें तीन गोल्ड, नौ सिल्वर और पांच ब्रॉन्ज़ मेडल शामिल हैं। गोल्ड मेडल मीराबाई चानू (महिलाओं का 48 किग्रा वेटलिफ्टिंग), शर्मिला धनखड़ (महिलाओं का शॉट पुट एफ 57) और दिलीप गावित (पुरुषों की 100 मीटर टी 47 दौड़) ने जीते हैं। भारत ने ऋषिकांत सिंह, मुथुपंडी राजा,ज्ञानेश्वरी यादव,सर्वेश कुशारे, वल्लुरी अजय बाबू,हरजिंदर कौर, गुलवीर सिंह,मुरली श्रीशंकर,मोहम्मद बासिल और लवप्रीत सिंह ने भी रजत पदक जीते हैं,जबकि झंडू कुमार,बिंद्यारानी देवी, शिल्पा के शायला और सीमा कालीरामना ने कांस्य पदक जीते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने की भेंट...छत्तीसगढ़ के विकास और 'बस्तर विजन' पर हुई विस्तृत चर्चा

शांति और विश्वास के साथ अब विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है बस्तर : मुख्यमंत्री साय

- **राजनांदगांव में 10,500 करोड़ की गैस आधारित यूरिया परियोजना,461 गांवों में स्थायी ग्रिड कनेक्टिविटी और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की स्थापना के लिए मांगा सहयोग**
- **मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष रखा बदलते बस्तर का रोडमैप**

रायपुर,31 जुलाई 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सौजन्य भेंट कर छत्तीसगढ़ के समग्र विकास, बस्तर के कायाकल्प तथा राज्य की महत्वपूर्ण अधोसंरचना एवं औद्योगिक परियोजनाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष बदलते छत्तीसगढ़ और विशेष रूप से बस्तर के विकास का रोडमैप प्रस्तुत करते हुए राज्य की तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से सहयोग का आग्रह किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सुरक्षा,विश्वास और विकास की समन्वित रणनीति के परिणामस्वरूप बस्तर आज व्यापक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। दशकों तक नक्सल हिंसा और विकास संबंधी चुनौतियों का सामना करने वाला यह क्षेत्र अब शिक्षा,स्वास्थ्य,सड़क,रेल,बिजली, हवाई संपर्क,आजीविका,खेल और पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार का लक्ष्य इस परिवर्तन को स्थायी बनाते हुए बस्तर को विकास की मुख्यधारा से पूरी तरह जोड़ना है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रायपुर अथवा बस्तर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की स्थापना के प्रस्ताव पर सकारात्मक पहल का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़,विशेषकर बस्तर और अन्य जनजातीय क्षेत्रों में औषधीय वनस्पतियों एवं पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान की समृद्ध विरासत है। राष्ट्रीय स्तर के आयुर्वेद संस्थान की स्थापना से चिकित्सा, अनुसंधान,शिक्षा और औषधीय वनस्पतियों पर आधारित स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए नई संभावनाएं विकसित होंगी।

मुख्यमंत्री साय ने राजनांदगांव में 10,500 करोड़ की यूरिया परियोजना के लिए शीघ्र मंजूरी का किया अनुरोध

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजनांदगांव में प्रस्तावित लगभग 10,500 करोड़ की गैस आधारित यूरिया परियोजना को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि परियोजना के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध करा दी गई है तथा राज्य सरकार के स्तर की आवश्यक स्वीकृतियां भी पूरी की जा चुकी हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के स्थापित होने से छत्तीसगढ़ सहित आसपास के क्षेत्रों के किसानों के लिए उर्वरक की उपलब्धता और बेहतर होगी। इसके साथ ही प्रदेश में औद्योगिक निवेश, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार तथा सहायक आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी।

461 गांवों को स्थायी विद्युत ग्रिड से जोड़ने के लिए मांगी विशेष सहायता

मुख्यमंत्री साय ने बस्तर सहित संवेदनशील क्षेत्रों के ऐसे 461 गांवों का विषय भी प्रधानमंत्री के समक्ष रखा, जहां पूर्व में सुरक्षा एवं भौगोलिक कारणों से विद्युत ग्रिड पहुंचाना संभव नहीं हो पाया था और वर्तमान में ऑफ-ग्रिड माध्यम से बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने इन गांवों को स्थायी विद्युत ग्रिड से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार से विशेष सहयोग का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थायी विद्युत आपूर्ति से इन क्षेत्रों में शिक्षा,स्वास्थ्य,संचार,आजीविका और लघु उद्यमों के विस्तार को गति मिलेगी तथा दूरस्थ अंचलों में विकास की प्रक्रिया और मजबूत होगी।

5,542 गांवों तक पहुंच रहा विकास, लगभग 39 लाख लोगों को लाभ

मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री के समक्ष 'बस्तर विजन' की विस्तृत जानकारी रखते हुए बताया कि 'नियद नेल्ला नार 2.0' और 'बस्त मुन्ने' के माध्यम से बस्तर संभाग के 5,542 गांवों में शासन की योजनाओं और सेवाओं का व्यापक क्रियान्वयन किया जा रहा है जिससे लगभग 39 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राशन, आयुष्मान भारत,जनधन खाते,वनाधिकार, प्रधानमंत्री आवास सहित केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। दूरस्थ और पूर्व में अत्यधिक संवेदनशील रहे गांवों में प्रशासन की पहुंच बढ़ने से शासन के प्रति विश्वास मजबूत हुआ है। मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री को बस्तर में शिक्षा के क्षेत्र में आए परिवर्तन की जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में वर्षों से बंद पड़े 421 स्कूलों को पुनः प्रारंभ किया गया है। जिन गांवों में कभी बच्चों के लिए नियमित शिक्षा तक पहुंच बड़ी चुनौती थी, वहां अब स्कूलों में फिर से पढ़ाई शुरू हुई है। उन्होंने बताया कि दंतेवाड़ा की तर्ज पर ओरछा और जगरगुंडा में नई एजुकेशन सिटी विकसित करने की दिशा में भी राज्य सरकार कार्य कर रही है।

'मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान' में 34 लाख से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच

मुख्यमंत्री साय ने स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की जानकारी देते हुए बताया कि 'मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान' के अंतर्गत अब तक 34 लाख से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच की जा चुकी है और आवश्यकता के अनुरूप उन्हें चिकित्सा सेवाओं से जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि बस्तर में चिकित्सा अधोसंरचना का लगातार विस्तार किया जा रहा है। जगदलपुर में सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के साथ गीदम में मेडिकल कॉलेज के माध्यम से क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है। राज्य सरकार नए मेडिकल कॉलेजों और आधुनिक स्वास्थ्य अधोसंरचना के विकास की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रही है।

सड़क,रेल,बिजली और हवाई संपर्क से बदल रही बस्तर की तस्वीर

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बस्तर के स्थायी विकास के लिए कनेक्टिविटी सबसे महत्वपूर्ण आधार है। इसी दृष्टि से सड़क,रेल,बिजली और हवाई संपर्क का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि लगभग 3,513 करोड़ की लागत से जगदलपुर-राघवाट रेललाइन परियोजना पर कार्य आगे बढ़ रहा है। इस रेल संपर्क से बस्तर के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई गति मिलेगी। जगदलपुर से नियमित हवाई सेवाओं के विस्तार की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री साय ने रायपुर-विशाखापट्टनम एक्सप्रेस-वे के अंतिम चरण की प्रगति तथा इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित बैराज परियोजना की जानकारी भी प्रधानमंत्री को दी। उन्होंने कहा कि बैराज परियोजना से लगभग 32 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे क्षेत्र के किसानों और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ मिलेगा।

बस्तर दशहरा को वैश्विक पर्यटन ब्रांड बनाने की दिशा में प्रयास

मुख्यमंत्री साय ने बस्तर की अनूठी जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और पर्यटन संभावनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि बस्तर दशहरा को वैश्विक पर्यटन ब्रांड के रूप में स्थापित करने की दिशा में योजनाबद्ध प्रयास किए जा रहे हैं। चित्रकोट और तीरथगढ़ जैसे विश्वस्तरीय प्राकृतिक पर्यटन स्थलों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर और प्रमुखता से स्थापित करने के लिए अधोसंरचना एवं सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बस्तर का विकास उसकी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान और प्रकृति के संरक्षण के साथ किया जा रहा है,ताकि विकास का लाभ स्थानीय समुदायों तक पहुंचे और रोजगार एवं आजीविका के नए अवसर सृजित हों।

छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात...बहुप्रतीक्षित डोंगरगढ़-कटघोरा रेल लाइन परियोजना को मिली स्वीकृति

रायपुर,31 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी सौगात के रूप में बहुप्रतीक्षित डोंगरगढ़-कटघोरा रेल लाइन परियोजना को स्वीकृति मिल गई है। नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय,सांसद संतोष पांडे और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू भी मौजूद रहे। बताया गया कि सांसद संतोष पांडे लंबे समय से लोकसभा में इस रेल परियोजना की मांग लगातार प्रभावी ढंग से उठाते रहे थे। केंद्र सरकार द्वारा परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद क्षेत्र के विकास की नई संभावनाएं खुल गई हैं। इस रेल लाइन के निर्माण से खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले समेत आसपास के क्षेत्रों को सीधा लाभ मिलेगा। परियोजना से उद्योग, व्यापार,पर्यटन और स्थानीय

रोजगार को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ क्षेत्रीय कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। राज्य सरकार का कहना है कि इस रेल परियोजना से न केवल परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी,बल्कि निवेश और आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी। स्थानीय लोगों को लंबे समय से इस परियोजना का इंतजार था,जो अब पूरा होने जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस स्वीकृति को छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय का आभार व्यक्त किया। वहीं,सांसद संतोष पांडे ने कहा कि यह क्षेत्र की जनता के लंबे संघर्ष और मांग का परिणाम है, जिससे आने वाले समय में विकास के नए द्वार खुलेंगे।

3 अगस्त को सीएम हाउस घेराव करेगी कांग्रेस

महंगी बिजली के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा आंदोलन..1 से 3 अगस्त तक प्रदेशभर में होगा प्रदर्शन

रायपुर,31 जुलाई 2026। प्रदेश में बढ़ते बिजली बिल को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने शुक्रवार को प्रेसवार्ता में कहा कि कांग्रेस 1 से 3 अगस्त तक पूरे प्रदेश में तीन दिवसीय चरणबद्ध आंदोलन चलाएगी। जिला मुख्यालयों पर प्रेसवार्ता,घर-घर जनसंपर्क और आवेदन अभियान के बाद 3 अगस्त को मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा। बैज ने कहा कि प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को लगातार अधिक बिल मिल रहे हैं। स्मार्ट मीटर और बिजली दरों में बढ़ोतरी से आम लोगों का घरेलू बजट बिगड़ गया है।

कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर गांव-गांव और शहर-शहर लोगों के बीच जाएगी और सरकार के खिलाफ जनमत तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पिछले कई महीनों से महंगी बिजली और स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर आंदोलन कर रही है। अब इसे प्रदेशव्यापी अभियान का रूप दिया जा रहा है, ताकि हर उपभोक्ता अपनी बात सरकार तक पहुंचा सके।

तीन दिन तक ऐसे चलेगा आंदोलन

1. अगस्त को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रेसवार्ता करेंगे। इसमें महंगी बिजली, बढ़े हुए बिजली बिल और स्मार्ट मीटर से जुड़ी शिकायतों को सामने रखा जाएगा।
2. अगस्त को कांग्रेस कार्यकर्ता घर-घर पहुंचेंगे। बिजली उपभोक्ताओं से संपर्क कर महंगे बिजली बिल और स्मार्ट मीटर के खिलाफ आवेदन भरवाए जाएंगे। इन आवेदनों के जरिए सरकार पर बिजली दरों की समीक्षा और उपभोक्ताओं को राहत देने का दबाव बनाया जाएगा।
3. अगस्त को प्रदेशभर से कांग्रेस कार्यकर्ता रायपुर पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। कांग्रेस का दावा है कि इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और बिजली उपभोक्ता शामिल होंगे।

बैज ने कहा कि कांग्रेस जनता की आवाज बनकर यह लड़ाई लड़ रही है। यदि सरकार बिजली दरों और बढ़े हुए बिलों पर राहत नहीं देती है, तो आंदोलन को आगे और तेज किया जाएगा।

चीटियों ने रोके मदर-चाइल्ड यूनिट ऑपरेशन,स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे सवाल

दुर्ग,31 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला अस्पताल से स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल की मदर-चाइल्ड यूनिट के ऑपरेशन थिएटर में अचानक बड़ी संख्या में चींटियां मिलने के बाद हड़कंप मच गया। संक्रमण के खतरे को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन को आनन-फानन में ओटी बंद करना पड़ा। इस घटना ने अस्पताल की साफ-सफाई व्यवस्था और मरीजों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिला अस्पताल के एमसीएच यूनिट का ऑपरेशन थिएटर पिछले तीन दिनों से बंद है। इसके कारण यहां होने वाली नियमित सर्जरी प्रभावित हो गई है। अस्पताल में औसतन हर दिन करीब पांच ऑपरेशन किए जाते थे, लेकिन ओटी बंद होने के कारण सभी सर्जरी को टालना पड़ रहा है। इससे मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।स्वास्थ्य विभाग की इस लापरवाही के कारण गंभीर मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। खासकर उन मरीजों को दिक्कत हो रही है, जिन्हें समय पर ऑपरेशन की जरूरत थी। बावजूद इसके, घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन की ओर से कोई बड़ी कार्रवाई सामने नहीं आई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने सिजेरियन डिलीवरी के ऑपरेशन को दूसरे बड़े ऑपरेशन थिएटर यानी मेजर ओटी में स्थानांतरित कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह कदम उठाया गया है।हालांकि मेजर ओटी में पहले से ही सीमित संसाधन और जगह उपलब्ध है।

सहायक मत्स्य अधिकारी भर्ती परीक्षा 2025 का परिणाम हाईकोर्ट ने किया रद्द,दोबारा होगी प्रक्रिया

रायपुर,31 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य की सहायक मत्स्य अधिकारी भर्ती परीक्षा 2025 की पूरी चयन प्रक्रिया और घोषित परीक्षा परिणाम को निरस्त कर दिया है। 31 जुलाई 2026 को सामने आए इस अहम फैसले में अदालत ने विभागीय लापरवाही, नियमों के उल्लंघन और पूर्व आदेशों की अनदेखी को आधार माना है।

जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की एकल पीठ ने उम्मीदवारों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य शासन को निर्देश दिया है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया अब निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से दोबारा आयोजित की जाए। इस फैसले से गलत प्रक्रिया का शिकार हुए पात्र अभ्यर्थियों को न्याय मिलने की नई उम्मीद जगी है। हाईकोर्ट में प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार, विभाग ने भर्ती प्रक्रियाओं के संचालन में वैधानिक नियमों को दरकिनार किया था। मत्स्य सेवा भर्ती नियम 2009 के तहत

चयन समिति में अधिकतम तीन सदस्यों का प्रावधान निर्धारित है। इसके विपरीत विभाग ने नियमों से परे जाकर पांच सदस्यीय समिति का गठन किया और साक्षात्कार आयोजित किए। सुनवाई के दौरान अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए टिप्पणी की कि जब कानून में किसी प्रक्रिया को पूरा करने का तरीका स्पष्ट रूप से तय हो, तो उसका अक्षरशः पालन अनिवार्य होता है। निर्धारित नियमों से बाहर जाकर बनाई गई समिति द्वारा किया गया चयन पूरी प्रक्रिया को अवैध और शून्य बना देता है। इस विवाद की जड़ें वर्ष 2014 की पुरानी भर्ती से जुड़ी हुई हैं, जब सहायक मत्स्य अधिकारी के 8 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ था।

उस समय उम्मीदवारों ने आरोप लगाया था कि सभी अर्हताएं पूरी करने के बावजूद उन्हें अनुचित तरीके से अपात्र करार दिया गया। यह मामला जब डिवीजन बेंच के समक्ष पहुंचा, तब अदालत ने राज्य सरकार को सभी आवेदकों के दस्तावेजों का समान रूप से पुनर्मूल्यांकन करने का आदेश दिया था। हालांकि, विभाग ने सभी आवेदनों की निष्पक्ष जांच करने के स्थान पर केवल प्रतीक्षा सूची (वेटिंग लिस्ट) के एक अभ्यर्थी से तुलना कर औपचारिकता पूरी कर ली, जिसे अदालत ने अपने आदेश का स्पष्ट उल्लंघन माना।

14.56 करोड़ के लोन घोटाले का मास्टरमाइंड अरेस्ट

फर्जी और बंद संस्थानों को दिलाए रुपए,180 खातों में गड़बड़ी,तमिलनाडु से पकड़ाया बैंक मैनेजर

बेमेतरा,31 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखा में हुए 14.56 करोड़ के कथित घोटाले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को अरेस्ट किया है। तत्कालीन शाखा प्रबंधक विनीत दास को तमिलनाडु के तंजावुर से गिरफ्तार किया गया। उसे ट्रांजिट रिमांड पर बेमेतरा लाया गया है। जांच में पता चला कि उसने बैंक के नियमों को नजरअंदाज कर फर्जी और बंद संस्थानों, स्वयं सहायता समूहों, किसान क्रेडिट कार्ड और कृषि योजनाओं के नाम पर करोड़ों रुपए के लोन मंजूर किए। इसके अलावा बिना खाताधारकों की जानकारी के पैसे ट्रांसफर करना, फर्जी जीएसटी नंबरों का इस्तेमाल करना और जरूरी जांच-पड़ताल किए बिना लोन मंजूर करने जैसी कई गड़बड़ियां भी सामने आई हैं।

पुलिस के अनुसार, अब आरोपी से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क और घोटाले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है। मामले में 4 बिचौलियों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। मामले की शुरुआत साल 2022 में हुई थी, जब इंडियन ओवरसीज बैंक की बेमेतरा शाखा के तत्कालीन प्रबंधक रज्जू पाटनवार ने शिकायत दर्ज कराई थी।

बिलासपुर सेंट्रल जेल में कैदी की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा,डीजीपी और गृह सचिव तलब

बिलासपुर,31 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर सेंट्रल जेल में हुई 34 वर्षीय श्रवण सूर्यवंशी की मौत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के डीजीपी और गृह सचिव को तलब किया है। दोनों वरिष्ठ अधिकारी 4 अगस्त 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के सामने उपस्थित होकर सरकार का पक्ष रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में हुई मौत के मामले में राज्य सरकार से पूछा है कि एफआईआर दर्ज करने और आपराधिक जांच शुरू करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। अदालत ने हाई कोर्ट द्वारा मृतक के परिवार को दिए गए एक लाख रुपये के मुआवजे को भी अपर्याप्त बताया है।

पत्नी और बेटियों ने दायर की थी याचिका : श्रवण सूर्यवंशी की पत्नी लहरा बाई ताम्रकार और उनकी दो नाबालिग

बेटियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से पेश हलफनामे पर नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि हलफनामे में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि हिरासत में मौत के मामले में एफआईआर दर्ज करने या आपराधिक जांच शुरू करने को लेकर क्या कार्रवाई की गई है। जानकारी के अनुसार, 18 जनवरी 2024 को बिलासपुर जिले की सीपत पुलिस ने श्रवण सूर्यवंशी को आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। उसके पास से 6 लीटर कच्ची महुआ शराब मिलने का आरोप था। गिरफ्तारी के बाद उसे बिलासपुर केंद्रीय जेल भेज दिया गया था।शादी 21 जनवरी को उसकी तबीयत अचानक खराब हुई,जिसके बाद उसे सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान 22 जनवरी की सुबह उसकी मौत हो गई।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)